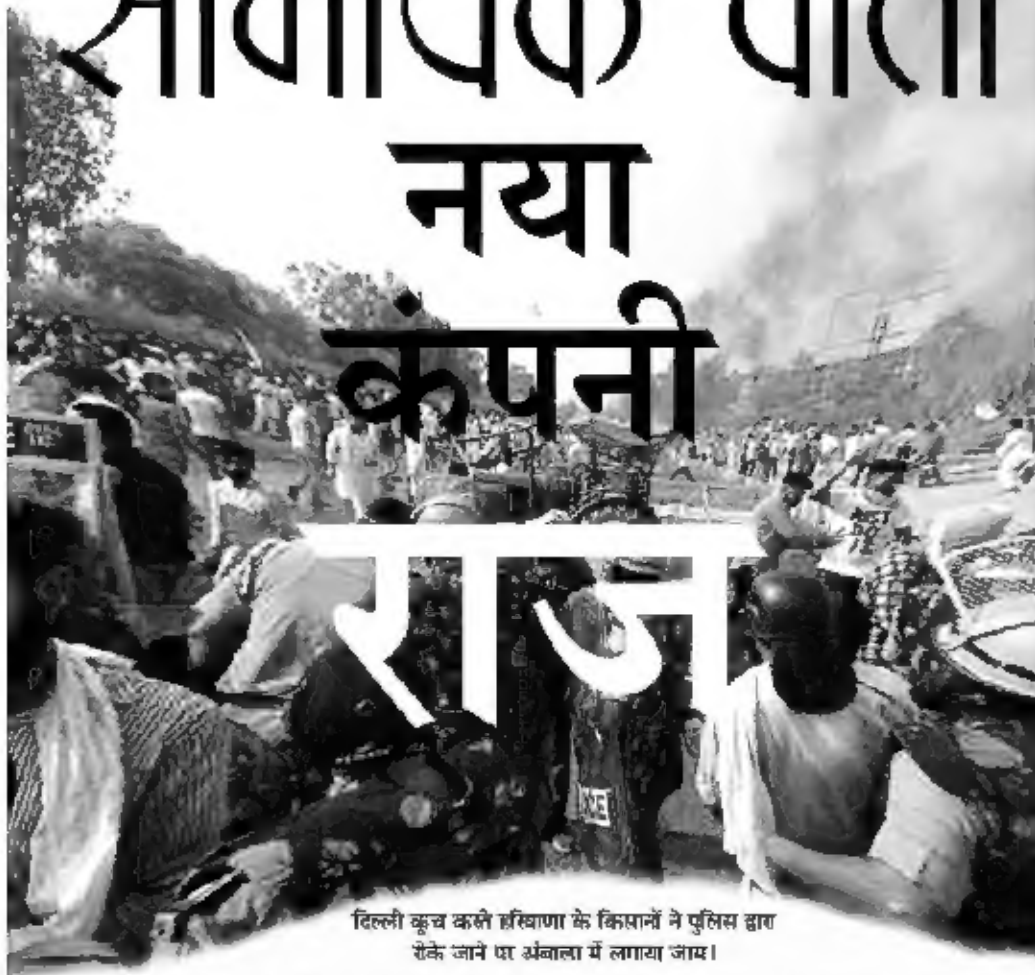


■ वर्ष 43, अंक 7, सितंबर 2020

■ मूल्य 20 रुपये

सामयिक वार्ता नया कंपनी राज



दिल्ली कूच कसे हलवाणा के किसानों ने पुलिस द्वारा
रोके जाने पर अंबाला में लगाया जाय।

किसान कंपनियों की गुलामी, मजदूर बेगारी को मजबूर

- नरेंद्र मोर्य की कविताएं ■ स्मृतिशेष : हरीश अड्यालकर, ध्रुव, रिचर्ड ग्रोव
- जो ज्यादा गरीबी में फंसे, उन्हीं पर जुल्म ■ कॉर्पोरेट खेती: बदल रहे कानून

कविता

नरेंद्र कुमार मौर्य की गजलें

छुपाये न छुपती खुशी...

छुपाये न सुपती खुशी पत्थरों की,
सुनाई पड़े है हसी पत्थरों की।

गिर एक दिन सर पे घेरे यकायक,
यही है मियाँ रहबरी पत्थरों की।

हमें नाव देकर के अहले सिंघासत,
दिखाती फिर इक नदी सरयों की।

यही देखना रह गया था खुदाया,
करे चाकरी आदमी पत्थरों की।

पड़े अक्स पे देख ले वू हजारों,
नहीं है कहीं भी कभी पत्थरों की।

कभी खर खोने पे खन्ना उगाकर,
करे है तदीया हरी पत्थरों की।

दुखों से है निस्वत न कुछ आंसुओं से,
मिली है हमें इक सदी पत्थरों की।

भला है हस्ते में यही दूर उनसे,
बुरी दोस्ती-दुश्मनी पत्थरों की।



उसे बातें बनाने...

उसे बातें बनाने की पड़ी है,
तुझे खाने कमाने की पड़ी है।

संभलता ही नहीं है घर हमारा,
मगर हमको जमाने की पड़ी है।

दिलों को बेचने निकले हैं आशिक,
मुहब्बत को बघाने की पड़ी है।

बनाकर एक दिन तुमको लतीफत,
उसे सबको हंसाने की पड़ी है।

न देखे दाग कोई भी दिलों के,
फरिश्तों को छुपाने की पड़ी है।

पिरासत की बड़ी जंगी इमारत
सिंघासत को गिराने की पड़ी है।

अजब है रुबरी तेरी अंधेर,
दुख तो बस डगने की पड़ी है।

वही जो ले गया दिन रात मेरे,
उसे जसबे दिखाने की पड़ी है।

उसी के पास आना चाहता हूँ,
जिसे बस दूर जाने की पड़ी है।

नहीं कोई मियाँ सुनने पे राजी,
सभी को बस सुनाने की पड़ी है।

कहीं कमबख्त जो लगता नहीं है,
उसी दिल को लगाने की पड़ी है।

अंधेरे में सभी खुश हैं तुझे क्यों,
परगों को जलाने की पड़ी है।

अपने प्रिय शायर
डॉ. राहत इंदौरी के नाम

मियाँ जिस दौर में रहत नहीं है,
हमें उस दौर की चाहत नहीं है।

अभी सूरज ने आंखें मीच ली हैं,
गजब है आपको हैरत नहीं है।

जिसे तुम पगड़ कर छी धूल जाओ,
सुनो ये शावरी है, खत नहीं है।

नहीं भारत किसी के नाप का है,
कहा सच झूठ की आदत नहीं है।

ज्वालात को गिरा सकती सिंघासत,
मिट दे जायरे ताकत नहीं है।

गजल कह कर सिखाये जो मुहब्बत,
सभी के पास ये दोलत नहीं है।

उन्हें भी वो बना सकता था इंसान,
फरिश्तों को मगर फुरसत नहीं है।

गलत को वो गलत कहता रहा है,
मगर उस झूठ में हिम्मत नहीं है।

समझ लो यार उसकी शावरी को,
मुहब्बत है कहीं नफरत नहीं है।

व्हो तो है अजोमुशान शावर,
उसे कहने में सच दिक्कत नहीं है।

उसे क्यों गलियाँ तुम दे रहे हो,
बड़े कमजोर हो, गैरत नहीं है।

सामयिक वार्ता अब
www.lohiatoday.com
पर भी पढ़ सकते हैं।

इस अंक में



जो गरीबी के जंजाल में फंसे,
उन्हीं पर जुल्म

08

कॉरपोरेट खेती के लिए बदले जा
रहे कानून

14

कोविड-19 महामारी के प्रभाव
और आगे की राह

16

आजादी के आंदोलन में कांग्रेस
सोशलिस्ट पार्टी का योगदान

18

हागिया सोफिया का संग्रहालय से
मस्जिद बनना: बदल रहा है समय

20

राजसत्ता, पूंजीसत्ता और धर्मसत्ता
के गठबंधन खोलती पुस्तक

22

सामयिक वार्ता

दिसंबर 2020, वर्ष 42, अंक 17

संस्थापक संपादक : किशन पट्टनायक

संपादक : अरुणानंद

संपादन सहायक

डॉ. बलवीर जैन, अरविन्द मोहन, हरिचोहन, राजेंद्र
राय, सत्येन्द्र रंजन, प्रियदर्शन, अरुण त्रिपाठी, प्रो. महेन्द्र
किशोर सिंह, लोकार्क द्विवेदी, संजय शर्मा, चंचल
पुस्तकी, कपिल कवर्गी, संजय भारती

अध्यक्ष मंडल

प्रतिनिधिमंडल मित्र, प्रो. कर्णधार उपाध्याय, मित्रता
रूप मन्त्रालय : राज्य मित्र

सदस्यमंडल : 2019, संपादक प्राणेश, पंडितमण्डल,
दिल्ली-110071

ईमेल : varta3@gmail.com,
ap.delhistate@gmail.com

सदस्यता शुल्क :

| | |
|-----------------------|------------|
| एक प्रति | 20 रुपये |
| वार्षिक शुल्क | 200 रुपये |
| संस्थान वार्षिक शुल्क | 300 रुपये |
| छह माता शुल्क | 1000 रुपये |
| मानविक शुल्क | 3000 रुपये |

खाता नाम : सामयिक वार्ता
या Samayik Varta

बैंक ऑफ बड़ोदा (Bank of Baroda)

खाता : सोनारपुर, वाराणसी (उ.प्र.)

Sonarpur, Varanasi (U.P.)

खाता संख्या : 4017010006458

IFSC Code : BARB0SONARP

(यहाँ दूसरे B के बाद बीरो है, जो नहीं,
S के बाद P (ओ) है।)

MICR CODE : 221012030

(इस खाते में पैसे जमा करने तथा ग्राहक के पते
की सूचना ई-मेल अवधि पोस्टाल
08785811730/08004085923 पर दें।)

संपादकीय

अब उठ खड़े होने का वक्त

यह इस सदी का कर्नवालिस पल है। उन्नीसवीं सदी में भूमि बंशोन्मूलन कामून लाकर जैसे किसानों की जमीन छीनने और उन्हें भूमिवाही जमींदारों के तहत पिछने को मजबूर कर दिया गया था, ठीक उसी तरह कृषि संबंधी तीन नए कानूनों के जरिए किसानों की उपज और खेतों पर भी उनके के जरिए मुट्ठीभर कंपनियों का राज का इंतजाम कर दिया गया है। वह 'राजना पूंजीवाद' का भी नायाब नमूना है, जिसको इस महाभारत, महाभरतों में भी संपत्तियों में इजाजत हो रहा है। शाब्दिक यही है आपदा में अवसर तलाशने का मंत्र, जिसे नॉर्ड मोटी कहते आए हैं। जब देखिए इस दौर में क्या हो रहा है। काले कानूनों के जरिए किसानों को कंपनियों को मजदूरी का बुरासा बना दिया गया, नए श्रम कानूनों के तहत मजदूरों के सदियों से हासिल हक छीन लिए गए। यह तो नमूना भर है। क्या हुआ और क्या हो रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं।

नोटबंदी के समय से रोजगार-नौकरी में शुरू हुई गिरावट देशव्यापी (लॉकडाउन) के दौरान और उसके बाद भ्रंशरूप से तेज हो गई है। कई आकलन बताते हैं कि इस दौरान पांच करोड़ से अधिक लोगों का रोजगार खत्म हुआ है। बिस्मय कर देने वाली -24 प्रतिशत की आर्थिक गिरावट इसी दौरान दर्ज की गई है। उच्च-मध्यम वर्ग और उससे नीचे जितने भी वर्ग बना लें, उनमें घनघोर निरक्षरता और बिंता व्याप्त है। रोजगार, नौकरी के साथ कुल रोजगार में 93 प्रतिशत हिस्सेदारी वाला असंगठित क्षेत्र कराह रहा है। देशव्यापी के दौरान हजारों किलोमीटर की पदयात्रा कर अपने गृहस्थानों को पहुंचा श्रमिक परिवार वहां भी बिना रोजी-रोजगार के है। मनरेगा में नाममात्र का काम है तो दूसरे छोटे मंदीले उद्योग-धंधे धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं। ऐसी हताशा की स्थिति में जो बढ़ रहा है, वह समाज और सरकारी तंत्र के प्रति अविश्वास है। समाज की निज और परत के भेद में बांटने की यह सबसे सुफेद परिस्थिति होती है और इसका फायदा वहाँ से सुधे नत्व उठ रहे हैं। समाज और जीवन के हर क्षेत्र में धीरे-धीरे के भाव को गहरा कर, काल्पनिक दुश्मन की छवि बनाकर उसे असंयत का जामा पहनाया जा रहा है, और उस दुश्मन के खिलाफ उन्माद पैदा कर राष्ट्रवाद और राष्ट्रियता की छवि चमकाने के प्रयास तेजी से चल रहे हैं। कई बार यह सफल होता दिख भी रहा है।

अतीत में वह आजगया हुआ नुस्खा है। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद पराजित जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों ने जब अपनी संधि थोपी तो जर्मनी में भाते असंतोष बनया। वह असंतोष रोजगार- उद्योग के ख़ाम होने और आर्थिक विपन्नता के कारण पूरे जर्मनी में आया था। लेकिन इस असंतोष का धुँकीकरण एक समुदाय के

खिलाफ करने में सफलता हासिल करके एडोल्फ हिटलर ने संसदीय रास्ते से जिस कूट राजनीति का सूत्रपात किया, उसकी मुलमन दशकों तक जर्मनी के साथ ही पूरी दुनिया को देखनी पड़ी। हिटलर का तो अपनी ही तरह का अंत हो गया, लेकिन उसकी विचारधारा के प्रसारक और उस रास्ते पर चलकर अपने समाजों में काल्पनिक दुश्मन खड़ा कर उस पर सामंतीक हथेली को जबरजट ठडहने की पूरी परंपरा बनी रही है। ऐसी मुहिम में कानून का शासन, लोकतंत्र, मानव अधिकार को उपहास की दृष्टि से देखा जाता है और उसके कमजोर पक्षों को अपने हित में साधने के बाद हिंसा के भाव से फेंक देने की प्रवृत्ति होती है। पहले से मौजूद राष्ट्रीय, सामाजिक तंत्र इसे रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनके सफल होने में बहुत संदेह रहता है। भारत के पड़ोसी देशों- पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान में स्वयं सामाजिक तंत्रों को ध्वस्त कर खड़िवादियों, कट्टरपंथियों और अमानवीय तत्वों के हाथों होने के उदाहरण हैं। तुर्की में हाल ही में दशकों पुरानी अतातुर्क की अवधारणा को ध्वस्त कर कट्टरवाद का अट्टहास लगाया सोनिया संग्रहालय मामले में देखा जा सकता है।

हम भारत में सीधे-सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका आदर्श हिटलर की नस्लीय शुद्धता की अवधारणा रही है। इस नस्लवाद में धर्म का सड़का लग जाए तो उनके लिए सोने पर सुहावा। तुरंत यह है कि ऐसी विचारधारा को बहुसंख्यक समुदाय में पीढ़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए छोटे पापों को जरूरी मानकर वैधानिकता मिल जाती है। ऐसी सामाजिक शक्ति पाकर वह बर्बर शक्ति अपने बर्बरतम रूप में अट्टहास करने लगती है। आज सत्ताधारी विचारधारा इसी निर्दोष अट्टहास में मगमूल है। यहां उदाहरण के रूप में हम पांच घटनाओं की प्रस्तुत करना चाहेंगे।

15 सितंबर को उच्चतम न्यायालय में एक ऐतिहासिक अंतरिम फैसला आया है। आरएसएस विचारधारा के सुदर्शन चैनल ने पिछले कुछ महीनों से ऐसा दुरंधिष्ठान चलाया कि मुसलमान देश की प्रतिष्ठित और सर्वोच्च नागरिक सेवा चयन संगठन संघ लोक सेवा आयोग में घुसपैठ कर रहे हैं। अपने अफवाही बिग्रेड के जरिए तथ्यहीन झूठ को रुज्जार चार बोलकर सही साबित करते हुए इसने कथित खोजी रिपोर्टिंग 'बिंदस बोल' की गुंथला शुरू कर इसमें वह खुल्ला किया कि बड़ी संख्या में मुसलमानों का इन सेवाओं में साजिरान चयन हो जाता है। इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के बाद केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने चैनल को कुटिल झूठ यह कहकर प्रदान कर दी कि प्रसारण के लिए

सामयिक घांटा अब www.lohiatoday.com पर भी पढ़ सकते हैं।

संपादकीय

कह जिम्मेदार होगा। उच्चतम अदालत में समाज के जिम्मेदार लोगों के जाने के बाद यह फैसला अर्था है। इसमें अदालत ने चैनल और सरकार को तमाचा मारते हुए इस प्रसारण पर रोक लगा दी है, हालांकि अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। अदालत से इस प्रसारण को तैमनस्य फैलाने वाला और एक समुदाय को लांछित करने के प्रयास के रूप में स्थापित कर दिया। यहां ध्यान देने की बात है कि जब चैनल के वकील ने कहा कि मंत्रालय की ओर से इस कार्यक्रम के प्रसारण की मंजूरी दी गई है तो शीर्ष अदालत को पीट ने पूछा कि क्या मंत्रालय ने इस अनुमति को देते समय अपने दिमाग का इस्तेमाल भी किया था। अदालत ने यह भी पूछा कि अभिव्यक्ति और प्रकाशिता की स्वतंत्रता के नाम पर क्या किसी पूरे समुदाय को लांछित करने की अनुमति दी जा सकती है? जाहिर है कि देश की आबादी में लगभग 15 प्रतिशत आबादी खले मुस्लिम समुदाय की इस सर्वोच्च और प्रभावी प्रशासनिक सेष में अधिकतम गणोदारी 4-5 प्रतिशत से अधिक नहीं रही है। यह न केवल एक पूरे समुदाय को बदनाम करने की साजिश है बल्कि देश की प्रतिष्ठित और अब तक स्वच्छ चवन प्रक्रिया वाली मानी जाने वाली संस्था यूनीवर्सल की छवि को भी बर्बाद करने का कुत्सित प्रयास है।

दूसरी घटना में, 15 सितंबर को ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य में मुगलकालीन संज्ञा वाले जगहों, वस्तुओं और ऐतिहासिक मठों के संस्थानों की सूची बनाने का आदेश दिया। घोषणा की है कि उन नपों को बदला जाएगा। आग का मुगल संग्रहालय नाम बदलकर शिवाजी संग्रहालय कर भी दिया गया है। वृषी सरकार तर्क यह दे रही है कि समाज और देश को मुलाम बनाने वाली शक्तियों के नाम हटाए जाएंगे। लेकिन क्या सरकार इसी तर्क के आधार पर जाजर को आमंत्रित करने वाले राणा सांगा, इल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेनापति शानसिंह और राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर में स्थापित मनु महायज्ञ की मूर्तियों को हटाने का समर्थन करेगी? अगर नहीं तो यह उम्मादी सरकार की समाज को दूषित करने भर की कार्रवाई मानी जाएगी। हम यहां डॉ. राममनोहर लोहिया की उस उक्ति का भी प्रसंगवश उल्लेख करना चाहेंगे कि 'हर हिन्दू को सम्झना चाहिए कि रजिया, शेरशाह, जायसी वगैरह हमारे पुरखे हैं। साथ ही हर मुसलमान को यह सीखना चाहिए कि राजनी, गेरी और बाबर लुटेरे थे और हमलावर थे। यह दोनों जुमले साथ-साथ ही हिंदू और मुसलमान के लिए।' लेकिन वृषी सरकार समाज बनाने नहीं तोड़ने वाली चिन्ता रखती है।

तीसरी घटना में, कुछ दिन पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विधानसभा के छात्रों के एक समूह 'सिंजड़ा तोड़' को जो प्रमुख कार्यकर्ताओं को विरपत्तारी को चलत उठाते हुए जमानत दे दी। अदालत ने यहां भी टिप्पणी की कि यह संबिधान प्रदान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि पुलिस द्वारा छात्रों पर लगाए गए नफरत फैलाने के आरोप बेनुविषाद हैं।

चौथी घटना में अलीगढ़ में छात्रों के बीच दिए भाषण को

यजमोह बताकर जेल में डाले गए गोरखपुर के चर्चित डॉक्टर काफिल को जमानत देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वृषी सरकार और उसकी पुलिस की मंशा को विदेवपूर्ण बताया। उच्च न्यायालय ने डॉ. काफिल की गिरफ्तारी को भी संबिधान और न्याय व्यवस्था का हनन बताया। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई की संबिधान विरुद्ध बताया। इस भाषण में डॉ. काफिल नामचीन शायरी के कुछ शेर बोलते बजर आ रहे हैं, जिन्हें पुलिस और जिलाधिकारी ने विदेवपूर्ण मानकर उन पर रामुका लगाया था। यहां भी वृषी सरकार को मुंह की खानी पड़ी और आधी रात को डॉ. काफिल को जेल से रिहा करना पड़ा।

पांचवी घटना में असम में रंगोली संस्था द्वारा प्रस्तुत मूवी को नफरत फैलाने वाला बताकर राज्य के डीजीपी द्वारा रोकें जाने को गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने तत्कालीन और सरकार की बदनीयती बताकर खारिज कर दिया। इस मूवी को केवल इसलिए रोका गया था कि उसमें अभिनय करने वाली नायिका हिन्दू समुदाय की थीं जबकि अभिनेता मुसलमान। कथानक के अनुसार नायक नायिका को मदद करता है और दोनों एक-दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन घृणा, संकीर्णता की धरतल पर खड़ी राज्य की भाजपा सरकार को यह कथानक लब जिह्म सदरखा लगा।

इन कुछ उदाहरणों पर से स्पष्ट होता है कि समाज में बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर जाकर नफरत और सामाजिक विद्वेष के बीज न केवल बोए जा रहे हैं बल्कि उनके प्रस्तुत-पुष्पित करने के दुरधि प्रयास भी किए जा रहे हैं। समाज के एक प्रभावशाली तबके के प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन के बिना यह संभव नहीं हो सकता है। साफ है कि दुष्ट अभिधान बिना किसी जिम्मेदारी के चल रहा है। समर्थन करने वालों को यह भी नहीं दीख रहा कि अंततः में वे भी इस कुटिल अभिधान का शिकार बनते रहे हैं। समाज और देश में विषमता विचार और संघर्षों के ध्वस्त हो जाने से यह अभिधान सामाजिक और राजनीतिक तौर पर फिलहाल बेखटके चल रहा है।

सवाल यह है कि यह विकट समय केवल अपने प्रतिपक्षियों को ही नहीं, बल्कि इनसे निपट लेने के बाद पूरे समाज और संस्कृति पर टूट पड़ने वाला है। इसका प्रतिरोध समय रहते जरूरी है। समाज को संघेत होने की जरूरत है। अगर समाज इसी तरह प्रपाद में बहकर इनके सारे व्यधिचारों की कथित 'बड़े उद्देश्य की पूर्ति में छोटे-मोटे पापों' के तौर पर देखता रहा और दूसरे समुदाय पर हो रहे नफरती हमलों से मजे लेता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब बकी समुदायों पर भी किसी न किसी बछने यह कहर टूटेगा। तब भारतीय समाज सनातन गरिया को खोकर उसी तरह की दुष्ट शक्तियों की कठपुतली बनकर रह जाएगा, जो आज हम अपने आसपास देख-सुन रहे हैं। ऐसे में जिम्मेदार समाज की ओर से प्रतिरोध का तंत्र फिर से संगठित करने की ऐतिहासिक जरूरत है। व्यक्तिवाद की सुखद चवसिया ओढ़े नागरिकों के लिए चेतावनी है कि वे शिक्षण, संगठन और संघर्ष को जाग्रत करने के ऐतिहासिक कर्तव्य का चलन करें और व्यक्तिवाद की खाल से अपने को बाहर निकालें। अन्यथा समय हाथ से निपन्न जाने पर अपने बस में कुछ नहीं रहेगा। समय तो उनका अपराध लिखेगा ही। ■

नजरिया

जीडीपी में गिरावट रोकना मुश्किल नहीं था

अप्रैल-जून तिमाही में देश की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में 24 फीसदी की रिकॉर्ड गिरावट आई है। यह गिरावट अन्य देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इसका कारण कोविड महामारी को ही माना जाता है पर भारत के परिप्रेक्ष्य में उससे भी बड़ा कारण नवउद्धारवादी नीतितंत्र है। गौरतलब है कि कोविड के पूर्व देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक सिकुड़न (स्लोडाउन) से त्रस्त थी, जिसका कारण समग्र मांग का अभाव था। इस तिमाही में कोरोना-जन्य नुकसान तो हुआ ही है; पर इससे भी ज्यादा नुकसान समग्र मांग के अभाव के कारण हुआ है।

बहुत से देशों ने काफी हद तक इस तरह के नुकसान से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने में कामयाबी हासिल की है। क्योंकि इन देशों ने लॉकडाउन के साथ ही व्यापक स्तर पर कल्याणकारी कार्य शुरू कर दिए थे। इनमें समुचित बेरोजगारी भत्ता प्रमुख रहा है। बेरोजगारी कारेंवासियों की समुचित मदद की भी व्यवस्था की गई है। इन कदमों से बेतरफा फायदा होता है: एक, मजदूरों और बेरोजगारी कारेंवासियों के परिवारों की गुजर-बसर का इंतजाम हो जाता है। दो, जनसाधारण के पास पर्याप्त क्रयशक्ति होने से समग्र मांग के अभाव की समस्या काफी हद तक नियंत्रित हो जाती है।

कल्याणकारी कार्यक्रमों से अर्थव्यवस्था में तरलता (लिक्विडिटी) में बढ़ोतरी होने पर भी वामों में ज्यादा उछाल नहीं आता है। बेरोजगारी भत्ता आदि के ट्रांसफर से हासिल नकदी से खरीदारी में बढ़ोतरी होती है, जिससे फैलाव (स्पिल ओवर) के असर से अर्थव्यवस्था में रोजगार और उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में इस तरह की परिस्थितियों में कीन्ज के गुणक प्रभाव की अपेक्षानुसार तरलता में बढ़ोतरी के जरिए सरकार द्वारा कल्याणकारी मर्दों पर खर्चें बढ़ाने से रोजगार और उत्पादन में वृद्धि होती है। कल्याणकारी नीतियों से कई देशों में कोरोना-जन्य महामंदी के नकारात्मक असर को काफी हद तक कम किया जा सका है।

भारत में तीस साल से कल्याणकारी नीतियों को ज्वरस्थित तरीके से नकारा जाता रहा है। वह प्रक्रिया वार्शिंगटन सन्मति पर आधारित नवउद्धारवादी सुधारों को अपनाने के फैसले के साथ शुरू हो गई थी। तब से सभी सरकारों ने एक जैसे आर्थिक नीतितंत्र पर अमल किया है। मौजूदा परिस्थितियों में भी कल्याणकारी नीतियों को नकारना काफी हैरान करने वाला फैसला है।

नवउद्धारवादी नीतियों से भारत में आर्थिक धुलौकरण अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। ऊपरी तबकों की 20 फीसदी आबादी की औसत आमदनी पिछले तबकों की 80 फीसदी की औसत आमदनी से दस गुना है और इस गैरबराबर संमृद्धि से आर्थिक संमृद्धि की रफ्तार पर ही ब्रेक लगना शुरू हो चुका है।

पिछले वित्त वर्ष की आर्थिक सुस्ती (स्लोअउन) की शुरुआती बजह कारों और एयर कंडीशनर जैसी विलास की वस्तुओं की बिक्री में आई गिरावट थी। पिछले दो-तीन दशकों के दौरान औद्योगिक विकास में ये उद्योग अग्रणी रहे हैं, क्योंकि इस दौरान इन वस्तुओं के बहुत से नए खरीदार उभर आए थे। पर इन वस्तुओं के खरीदारों (जोकि ऊपरी 20 फीसदी आबादी तक ही सीमित है) के संतृप्त (सेच्युरेशन) स्तर पर पहुंचने के साथ ही इन वस्तुओं की मांग में पिछले साल काफी कमी आ गई थी। इससे काफी व्यापक स्तर पर नकारात्मक असर पड़ा था। धुलौकृत संमृद्धि के परिप्रेक्ष्य में मौजूदा नीतियों के खते वह समस्या लाइलाज हो थी। इस समस्या के ऊपर कोरोना की समस्या आ खड़ी हुई है।

विगत तीन दशकों के पुनरुत्थलोकन से स्पष्ट है कि कल्याणकारी नीतियों से ही बराबरी और संमृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। नवउद्धारवादी नीतियों में धुलौकरण और इसके परिणामस्वरूप विकासहीनता (स्टेगनेशन) निहित है। इन वर्षों में सरकारी स्कूलों और अस्पतालों का विकास तो अवरुद्ध हुआ है और इनकी बहुत सी स्थापित इकाइयों को रोजमर्रा के कामों को करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि जरूरी संसाधनों की आपूर्ति नहीं की जा रही है। कई अस्पतालों में डॉक्टर और स्टाफ नहीं हैं तो कइयों में दवाइयां नहीं हैं। बहुत से स्कूलों का भी यही हाल है। सरकारी शिक्षण सुविधाओं के अभाव के कारण देश में अशिक्षित और अकुशल श्रमिकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे जनसांख्यिकीय फायदे (डेमोग्रफिक डिविडेन्ड) की उम्मीद पर पानी फिरता नजर आ रहा है।

सदियों के संघर्ष से हासिल मजदूर हक छीन लिए गए

जिन श्रम कानूनों में उदारीकरण के दौर के बाद से ही बदलाव के लिए नव-पूंजीवाद के पैरोकार गला फाड़ते रहे हैं, लेकिन कोई सरकार, पहले कार्यकाल में मोदी भी नहीं, इनमें बदलाव की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी, कोरोना वायरस जैसी आपदा के बखाने यह कर दिया गया है। अब 500 तक कामगार वाली इकाइयों को नौकरी से हटाने के लिए कोई कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। यानी मजदूर को कोई कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा। सदियों के संघर्ष से हासिल अधिकार छीन लिए गए। यह तो अभी शुरुआत है, जो होगा उसकी तत्वीर खासकर उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही पेश कर चुकी है। आठ घंटे के बदले 12 घंटे काम और पांच खल तक नौकरी फक्की न होने को कानूनी रूप देने की कोशिश फिलहाल तो टल गई है, लेकिन अगली बार वह नहीं होगा, इससे कहा इनकार किया जा सकता है। यही नहीं, अब आगे मजदूर संघ बनाने पर भी पान्दी लग जाए, तो हड़त नहीं होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर यह नई बेगारी प्रथा की शुरुआत जैसा है, जो अंग्रेजों ने ही शुरू किया था। क्या अब भी लोगों को आवाज नहीं उठानी चाहिए।

नजरिया

नशे में बॉलीवुड और झूमते मीडिया चैनल

बमक भर्त्सना के उदाहरण के दौर पर फट्टा और रट्टा जाने वाला कथिप्रवर बिहारी का दोहा-कनक कनक ते सौ गुनी मादका अधिकार, वा खाए बौराव जग वा फाए बौराव : सुशांत सिंह राजपूत, उनकी प्रेमिका रिया चक्रवर्ती और उग्र राष्ट्रवादी बख्तबख्शी के कारण चर्चा में आई कंगना रणवत के आरोपों के कारण चल रहे क्रूर और सिहरन पैदा करने वाले झूमे पर न्याय सदीक बैठता है। कंगना रणवत का यह आरोप एकदम गलत नहीं है कि बॉलीवुड में नशा करने वाले लोग हैं, लेकिन उनकी इस बात में सनसनी यह अतिरिक्त है कि बॉलीवुड के 99 प्रतिशत लोग नशीली दवाओं का सेवन करते हैं। इतना ही नहीं, इसी आधार पर आगे बढ़कर उन्होंने बॉलीवुड को बिनी पाकिस्तान कहकर एक और विवाद खड़ा कर दिया है। इस पर शिवसेना नेताओं की प्रतिक्रिया बेस्तेरी है, जेसी देश के समान चैनल सिया चक्रवर्ती को लेकर कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत जैसे प्रतिभाशाली कलाकार की आत्महत्या दुःखद और बेचैन करने वाली है। उसका कारण अवसाद था या उन्हें नशे का आदी बनने वाली संघत, इसकी जांच भी एक संवेदनशील जांच है और इससे हमारे समाज और युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया भी। लेकिन इस पूरी जांच को जिस तरह भाजपा ने बिहार चुनाव में भावनात्मक लाभ उठाने के लिए सनसनीखेज बना दिया है, उसमें बड़ी लगता है कि चरस, गांजे और कोकीन से ज्यादा बॉलीवुड सत्ता और गैरभर के नशे का शिकार है।

नास्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस मामले में अब तक रिया चक्रवर्ती समेत आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। रिया का जितना दोष है उतनी सजा उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन सुरांत सिंह राजपूत का जितना दोष था उसकी सजा अब फिले देंगे। शायद लोग यह कह कर छुट्टी पा लेंगे कि उनकी बीता ही उनकी सजा थी। लेकिन जो मल्टी सुशांत ने की होगी उसकी सजा रिया को केवल इसलिए दी जाए कि उसने उनसे प्रेम किया और साथ रह ली थी। एक लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है, यह नाजबयज है। केंद्र में सत्ता में बैठी और बिहार में फिर सत्ता में आने को आगवाही पर्व अपने चहेते चैनलों के एंकरों से बिहार से देश भर के वातावरण में जो नशा पैदा कर रहे हैं वह बॉलीवुड के नशे से ज्यादा घातक है। क्योंकि बॉलीवुड का नशा तो संजय दत्त, फरदीन खान, रणवीर कपूर, इनी सिंह और प्रतीक बब्बर जैसे कलाकारों के व्यक्तिगत इलाज से ठीक हो जाएगा, लेकिन लोकतंत्र नाग्य विरोध और सत्ता को किसी कीमत पर प्राप्त करने का जो नशा चढ़ेगा, वह तो पूरे देश का नशा करके मारिगा। बॉलीवुड में नशे की प्रवृत्ति पुरानी है और उसका इलाज सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के मामले से नहीं हो जाएगा। उसके लिए लंबा इलाज करना होगा। संजय दत्त ने स्वीकार किया है कि जब उनके पिता सुनील दत्त उनका इलाज करने उन्हें अमेरिका ले गए तो अस्पताल

में उन्हें एक फार्म दिया गया। उस फार्म में यह भरना था कि उन्होंने कौन सा नशा किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि संजय दत्त ने उन सभी दवाओं पर सही लगाया जो उस फार्म में दर्ज थीं, क्योंकि उन्होंने हर तरह का नशा किया था। फरदीन खान तो 2001 में कोकीन खाते-पाने में अपराधी पाए गए थे। रणवीर कपूर ने माना कि उन्होंने 12 साल की उम्र से नशा करना शुरू किया था।

जबकि है कि नशा बॉलीवुड में हो या किसी शैक्षणिक संस्थान में, उससे मुक्ति दिलाने के लिए उसके जिम्मेदार लोगों को आगे आना चाहिए। पंजाब तो पूरा प्रांत ही नशे की चपेट में है और सरकार बदलने के बावजूद उससे मुक्ति नहीं मिल रही है। इसके बावजूद नशे से मुक्ति दिलाने का कार्यक्रम नशा करने नहीं किया जाना चाहिए उसे होशोहवास में करना चाहिए। नशे में फंसा हुआ व्यक्ति समाज का दुश्मन नहीं है और न हो उसे उलौड़ित किया जाना चाहिए। वह हमदर्दी का हकदार है और कानून को अपना काम करते हुए सनसनी से बचना चाहिए। नहीं तो शरबी फिल्म का वह गीत प्रासंगिक हो उठेगा कि नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा।

महामारी और महामंदी की दोहरी व्यथा में देश

भारतीय आर्थिकज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएयआर) के पहले सीरे सर्वे पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार, मई-2020 की शुरुआत तक देश में अनुमानतः 64 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे। इसका मतलब है कि उस घबराहट तक से लोग कोरोना के संक्रमण की चपेट में आए, लेकिन 5-7 दिनों के अंदर इन लोगों में एंटीबायोजी बनने शुरू हो जाने से वायरस इनके शरीर में पनप नहीं पाया था। सीरे सर्वे से यह पता लगता है कि इतने लोगों के शरीर में कोरोना के लिए एंटीबायोजी बनी हैं।

लॉकडाउन-1 और लॉकडाउन-2 के 40 दिनों में पहचाने गए संक्रमितों की संख्या 42 हजार थी और इन्हीं दिनों में किए गए सीरे सर्वे के अनुसार यह तादाद अनुमानतः 64 लाख थी। जबकि है कड़े लॉकडाउन से संक्रमण के फैलाव पर अंकुश नहीं लगाया जा सका। लॉकडाउन एक आजमाई हुई सशक्त नीति है। भारत इस मामले में अपवाद क्यों है? इसका कारण है- पूरक नीतियों के साथ ही लॉकडाउन प्रभावी होता है। जिन देशों ने लॉकडाउन के साथ प्रभावित आबादी की गुजर-बसर के लिए र्वाचित बेरोजगारी भत्ता आदि की समुचित व्यवस्था की थी, वहां इसका उल्लेखनीय असर हुआ है।

भारत में गुजर-बसर की व्यवस्था न होने से बहुत से प्रवासी श्रमिकों का जिस तादाद में पलायन हुआ है, उससे लॉकडाउन जैसा सशक्त कदम भी प्रभावहीन हो गया है और देश महामारी और महामंदी की दोहरी व्यथा में धंसता जा रहा है। पांच माह बीत जाने पर भी स्थिति सुधारने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं, यह बहुत चिंता का विषय है।

किसान-मजदूर

जो गरीबी के जंजाल में फंसे, उन्हीं पर जुल्म

बलबीर जैन

शाबाश सरकार बहादुर! जिनकी महामारी और देशबंध से रोजी-रोटी छिनी, उन्हीं को और मजबूर करने की अर्थनीति तो लाजवाब है। मजदूरों के हक छीनने के लिए श्रम कानूनों को बदल दिया गया और किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य और आस-पास की गंडी की सुविधा भी छीन ली गई। इस पूरे महामंदी के दौर में एकमात्र कृषि क्षेत्र ही ऐसा है, जहां थोड़ी सकारात्मकता दिख रही है तो अब उसी का दोहन करना है। हालांकि इस वक्त दोसरी विपदा के कारण देश बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एक तरफ कोविड-19 महामारी के फैलने का सिलसिला रोकना नहीं जा सका है तो दूसरी तरफ, अनादी के एक बड़े हिस्से की रोजी-रोटी की समस्या दिन-ब-दिन विषम होती जा रही है। पांच महीने से ज्यादा अरसे की बेरोजगारी से करोड़ों परिवार गरीबी की चपेट में आते जा रहे हैं। इन प्रभावित परिवारों को समुचित मदद नहीं मिलने से दीर्घकालिक गरीबी में बहुत ज्यादा इजाफे की आशंका बलवती हो गई है।

किस तबके को महामारी ने किस कदर प्रभावित किया है: इसको जानने के लिए महामारी से उत्पन्न महामंदी के संरचनात्मक प्रभावों को समझना जरूरी है। कृषि, किराना, खाद्य पदार्थ, दवाइयों के कारोबार के अलावा लगभग सभी कारोबार में उत्पादन घटा है। होटल, रेस्तरां, पर्यटन,

एयरलाइन, बस सेवाएं, टैक्सी सेवाएं आदि सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कई कारोबार बंद पड़े हैं। टेक्सटाइल जैसे उद्योगों में भी आर्थिक क्षमता से भी कम उत्पादन हो रहा है।

महामंदी के साथ महामंदी का दौर भी शुरू हो गया है, जिसकी चपेट में गैर-कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा आ चुका है। कृषि क्षेत्र पर देश की आधी आबादी निर्भर है, पर इस क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में मात्र 17 फीसदी योगदान है। इस तरह कृषि क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आमदनी देश की औसत आमदनी के तकरीबन तीसरे हिस्से के बराबर है। जबकि गैर-कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आमदनी कृषि क्षेत्र के मुकाबले तकरीबन पांच गुना है। इससे दो बातें स्पष्ट हैं- पहली, कृषि क्षेत्र में औसत आमदनी का स्तर इतना कम है कि इस क्षेत्र के द्वारा

देश को महामंदी से उबारने में ज्यादा भूमिका की उम्मीद नहीं की जा सकती है। दूसरी, कृषि क्षेत्र की यह कमजोर स्थिति और कृषि क्षेत्र और गैर-कृषि क्षेत्र के बीच इतनी ज्यादा गैर-बराबरी विगत 70 साल की कृषि-विरोधी नीतियों का ही नतीजा है। समाजवादी चिन्तक सचिदानंद सिन्हा की चर्चित पुस्तकों: 'इंटरनल कालोनी' (1973) और 'बिटर हावेस्ट' (1975) में इस गैर-बराबरी का विश्लेषण किया गया है और उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं।

गैर-बराबरी का सिलसिला इससे भी आगे है। गैर-कृषि क्षेत्र का अंदाजन 60 फीसदी हिस्सा अर्थात देश की आबादी का 30 फीसदी हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र (इन्फारमल सेक्टर) में है। कृषि क्षेत्र को 50 फीसदी और गैर-कृषि क्षेत्र को 30 फीसदी आबादी (इसमें शहरी आबादी 15 से 20 फीसदी के बीच और ग्रामीण आबादी 10 से 15 फीसदी के बीच है) को मिलकर देश की 80 फीसदी आबादी को अनौपचारिक क्षेत्र में गिना जाता है। महामंदी का सर्वाधिक असर गैर-कृषि अनौपचारिक क्षेत्र के इन्हीं 30 फीसदी लोगों पर पड़ा है।

अनौपचारिक क्षेत्र का अखलौकन : अनौपचारिक क्षेत्र में देश की अंदाजन 80 फीसदी आबादी है। इनको आमदनी का स्तर क्या है, इसकी प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। दरअसल अनौपचारिक क्षेत्र को परिभाषित वो 1970 के दशक में ही कर दिया गया था और इस पर काफी शोध भी हुआ है। असंगठित और गैर-

एक तरफ अनौपचारिक क्षेत्र में देश की 80 फीसदी आबादी है, जिनको औसत आमदनी का मात्र तीसरा हिस्सा ही मयस्सर है तो दूसरी तरफ देश की धनी 20 फीसदी आबादी है, जिनको औसत आमदनी का तीन गुना से भी ज्यादा मिलता है।

किसान-मजदूर

पंजीकृत (एस्टिब्लिशमेंट ऐक्ट के संदर्भ में) क्षेत्र में कार्यरत आबादी को इसमें गिना जाता है। गैर-पंजीकृत इकाइयों के कर्मचारी, रिटायर्ड श्रमिक, छिप्टपुट काम करने वाले, घरों में पूर्णकालिक या अल्पकालिक तरीके से काम करने वाले, फेरों वाले, डेले वाले, निक्शा चालक, स्व-रोजगारो कारोबारो (जैसे कि सब्जी विक्रेता) आदि को इसमें गिना जाता है। इसमें ऐसे कारोबार गिने जाते हैं, जिनके लिए बहुत कम पूंजी चाहिए और इसे शुरू करने में कोई ठेक-टोक नहीं हो। इनमें स्वयं और परिवार के सदस्य ही काम करते हैं। गैर-पंजीकृत होने से इस क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि इस क्षेत्र में नियोजित और कर्मचारों के मध्य कोई लिखित अनुबंध भी नहीं किया जाता है। इस कारण इस क्षेत्र में न्यूनतम श्रमिकों संबंधी कानून लागू नहीं ले पाते हैं। कर्मचारों राज्य योगा और कर्मचारों भविष्य निधि की सुविधा भी नहीं मिलती है।

अनौपचारिक क्षेत्र को लेकर आधिकारिक तौर पर देशव्यापी स्तर पर किसी प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यहाँ तक कि इस क्षेत्र की कुल आबादी के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं। 2008 में पारित असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा ऐक्ट के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पंजीकृत करके उन्हें स्मार्ट कार्ड मुहैया कराने का प्रावधान है। इन कार्डों से अनौपचारिक क्षेत्र के बारे में प्रामाणिक जानकारी मिल सकती थी, पर जाह्न वर्ष बीत जाने के बाद भी इस कानून को अमल में नहीं लाया गया है। वैसे देशव्यापी स्तर पर अनौपचारिक क्षेत्र की समुचित जानकारी जुटाना सरकार के लिए कोई दुष्कर कार्य नहीं है। डिजिटल हेल्थ कार्ड की वर्ज पर डिजिटल रोजगार फ़ार्ड भी बनाया जा सकता है।

अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर आबादी के बारे में कई अनुमान लगाए गए हैं, जो कि देश की आबादी के 75 से 92 फीसदी के बीच हैं। इन अनुमानों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने पर 80 फीसदी (60 फीसदी ग्रामीण और 20 फीसदी शहरी) का अनुमान तर्कसंगत जान पड़ता है।

अनौपचारिक क्षेत्र के लिए आय की जाबत भी देशव्यापी स्तर पर जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस संदर्भ में 2015-16 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा अनियमित गैर-कृषि क्षेत्र के उद्योगों के सर्वेक्षण का उल्लेख किया जा सकता है। इसके अनुसार इन उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को औसत सालाना तनख्वाह 87,544 रुपये थी। उसी वर्ष देश की प्रति व्यक्ति आमदनी 94,797 रुपये थी। श्रमिक परिवारों के सदस्यों की औसत संख्या तीन मानते हुए इन श्रमिक परिवारों की प्रति व्यक्ति आमदनी 29,181

सरकार के दावों के बावजूद बहुत से जरूरतमंदों, खासकर प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त अनाज नहीं मिल रहा है। 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों में से 2 करोड़ 51 लाख को ही मुफ्त अनाज मुहैया कराया जा रहा है।

रुपये के बराबर आती है और यह रकम देश की प्रति व्यक्ति आमदनी के तीसरे हिस्से से भी कम है।

नियमित रोजगार के कारण उपभोक्ता श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र के बहुतेरे अन्य श्रमिकों से बेहतर स्थिति में हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में ज्यादातर अकुशल श्रमिक हैं। इनमें कुछ ही राज मिस्त्री, पलम्बर, इलेक्ट्रिशियन जैसे कौशल वाले काम करने के काबिल हैं। अकुशल श्रमिकों में से कुछ तो नियमित रोजगार पाने में कामयाब हो जाते हैं, बाकी लोग दिहाड़ी काम या छिप्टपुट कामों से गुजर-बसर करते हैं। एक ही औद्योगिक अथवा व्यापारिक इकाई में लगातार कई वर्ष कार्यरत रहने से अनुभवजन्य प्रशिक्षण के कारण इन कर्मचारियों की उत्पादकता और

आमदनी बाकी श्रमिकों के मुकाबले ज्यादा ही होती है।

इस तरह अनौपचारिक क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आमदनी 2015-16 में 29,181 रुपये से कम ही थी, अर्थात उनकी औसत आमदनी देश की औसत आमदनी के तीसरे हिस्से से भी कम है।

इस तरह देश को 80 फीसदी आबादी का देश की राष्ट्रीय आय में हिस्सा तकरीबन 27 फीसदी (कृषि क्षेत्र का 17 फीसदी और गैर-कृषि क्षेत्र का 10 फीसदी) या इससे भी कम है। सबसे घनी 20 फीसदी आबादी की देश की कुल आमदनी में हिस्सेदारी 70 फीसदी से भी ज्यादा है। जाहिर है कि भारत में आय के वितरण की बैरबराबरी चार स्तर तक पहुँच चुकी है और देश में बुनियादी की प्रक्रिया एक पिताजनक शक्ल ले चुकी है। एक तरफ अनौपचारिक क्षेत्र में देश की 80 फीसदी आबादी है, जिनको औसत आमदनी का मात्र तीसरा हिस्सा ही वक्कर है तो दूसरी तरफ देश की घनी 20 फीसदी आबादी है, जिनको औसत आमदनी चार गुना से भी ज्यादा मिलता है। इन घने 20 फीसदी की औसत आमदनी देश की बाकी 80 फीसदी की औसत आमदनी का दस गुना है।

मौजूदा महापंदी का सबसे ज्यादा असर शहरी अनौपचारिक क्षेत्र पर पड़ा है। इस वकत बहुत लोगों के काम-धंधे बंद हैं और बहुत का रोजगार खिन गया है। ये लोग सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं और इनमें ज्यादा के पास न तो संरक्षण है ना ही अचल (जमीन-जायदद आदि) और चल (बचत आदि) परिसंपत्तियाँ हैं। सरकार के दावों के बावजूद बहुत से जरूरतमंदों, खासकर प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त अनाज नहीं मिल रहा है। 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों में से 2 करोड़ 51 लाख को ही मुफ्त अनाज मुहैया कराया जा रहा है। अन्य बुनियादी जरूरतों के मामलों में सरकारी सहायता का इंतजाम नहीं है। परिणामस्वरूप इस वकत शहरी अनौपचारिक क्षेत्र की आबादी का बड़ा हिस्सा गहरे संकट में है। उनमें एक बड़ा हिस्सा कर्ज की दलदल में फँसता जा रहा है, जिसका मतलब दीर्घकालिक गरीबी है। बहुत से परिवार तो

किसान-मजदूर

कई तरह की बुनियादी जरूरतों से महकम है, क्योंकि उन्हें उधार भी नहीं मिल पा रहा है। इस वंचित तबके की जरूरतों पर तबकों को नहीं दी जा रही है, यह सबल बहुत हैरान और परेशान करने वाला है।

सरप्लस दूध से संचित खाद्य पदार्थ बन सकता था : महामंदी का असर गैर-कृषि ग्रामीण काम-धंधों पर भी पड़ा है। देश के करोड़ों ग्रामीण परिवार अपनी जीविका के लिए दूध उत्पादन पर निर्भर हैं। इनमें मुख्यतः भूमिहीन, सीमांत और लघु किसान हैं। वैसे महामंदी का दूध उत्पादन पर खास असर नहीं पड़ा है। पर इसकी खपत में काफी कमी आई है। होटलों,

गैर-पंजीकृत इकाइयों के कर्मचारी, दिहाड़ी श्रमिक, छिटपुट काम करने वाले, घरों में पूर्णकालिक या अल्पकालिक तरीके से काम करने वाले, फेरी वाले, ठेले वाले, रिक्शा चालक, स्व-रोजगारी कारोबारी (जैसे कि सब्जी विक्रेता) आदि को इसमें गिना जाता है।

रेस्तरांओं, हलवाई की दुकानों, सामाजिक समारोहों- जैसे धोक उपभोक्ताओं की मांग, में भारी गिरावट आई है। दूध की आपूर्ति ज्यादातर डेक्कियों के माध्यम से होती है। महामंदी के शुरुआती दिनों में कई डेक्कियों ने दूध के अधिशेष (सरप्लस) को खरीद कर उसे सूखा दूध पाउडर, ची, पम्पकन जैसे संचित करने योग्य उत्पादों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। पर इन वस्तुओं के अनबिके स्टॉक में अत्यधिक वृद्धि हो जाने पर उन्होंने अतिरिक्त खरीद की प्रक्रिया ही बंद कर दी। अनबिके दूध के कारण तमों में 15 से 30 फीसदी की गिरावट से स्थिति काफी चिंतजनक हो गई है। सरकारी समर्थन से इस मसले को हल किया जा सकता था।



सरकार समुचित पैमाने पर सूखा दूध पाउडर खरीद सकती है, जिसे महामंदी के खतम होने पर स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। सहकारी क्षेत्र में कार्यरत संगठनों ने यह सुझाव दिया है, पर इस मामले में भी सरकारी रुझ हैरान और परेशान करने वाला है।

हथकरघा उद्योग संकट में, सेवा क्षेत्र भी प्रभावित : कुटीर उद्योगों पर भी महामंदी का बहुत पड़ा असर पड़ा है। 32 लाख हथकरघा कारीगरों की छलत भी काफी तबलीफदेह है। इनमें बहुत तो कर्ज लेने को मजबूर हैं। सेवाजो के क्षेत्र पर भी महामंदी का असर पड़ा है। कई निजी स्कूलों के अध्यापकों को पिछले तीन-चार माह से वेतन नहीं मिला है। ये स्कूल स्व-वित्त पोषित हैं और इनको इस दौरान फीस की अदायगी नहीं हुई है। कई स्कूल तो किराया आदि भी नहीं दे पा रहे हैं। इन स्कूलों में ज्यादातर छात्र निम्न-मध्यम वर्ग के हैं। ऐसे स्कूलों की ताखद काफी है।

मध्यम, लघु, घुसम उद्योगों पर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अनुमान है कि 40 फीसदी बड़ी औद्योगिक इकाइयां महामंदी से

बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। कारोबार बंद होने पर भी कई तरह के स्थिर खर्च कारोबारियों को वहन करने पड़ते हैं। जैसे- किराया, ब्याज, लाइसेंस फीस आदि। महामंदी का होटल, रेस्तरां, एयरलाइंस, बस-टैक्सी ऑपरेटर, ट्रैसपोर्ट आदि पर बहुत ज्यादा असर हुआ है और इस कारण कई इकाइयों के बंद होने का खतरा भी मंडग रहा है। निजी क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में स्टाफ को हटाया गया है। बहुत लोग बकानों, मोटर वाहन आदि के कर्ज की फिस्तों के भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं।

31 अगस्त को कितना भुगतान में स्थगन (मॉरटोरियम) की अवधि खत्म हो रही है और अगर इसे आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो ट्रैसपोर्टर तकरीबन 45,000 से 50,000 इकों को फाइनेंसों को वापस कर सकते हैं। कारोबारी, वेतनभोगी, व्यवसायी आदि सभी क्षेत्र महामंदी से त्रस्त हैं। महामंदी-जन्य जोखिमों से कैसे निबट ना सकता है, इनकी लागतों को कौन और कैसे वहन करेगा? इन नीतिगत सबलों पर स्पष्ट नीति अपनाकर उसे शीघ्र अमल में लाना निहायत जरूरी है।

आर्थिक पैकज : 25 मार्च को

अमानक दशवर्षीय लोकछावण की घोषणा की गई और 26 मार्च को 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये के पैकेज को 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' की घोषणा की गई थी। इसके अंतर्गत मनोरा की मजदूरी दर 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये की गई है। सभी छोटे किसानों को 2000 रुपये दिए जाने की व्यवस्था की गई है। जन धन योजना के अंतर्गत खातधारी महिलाओं को तीन माह के लिए 500 रुपये प्रति माह, गरीब, विधवा, विधवा और बुजुर्गों को एकमुस्त 1000 रुपये देने की व्यवस्था की गई है। मुफ्त गैस सिलेंडर दिलाने वाली उच्चला योजना को भी इसी पैकेज में गिना गया है।

12 मई से 18 मई के दौरान पांच अंशों में वित्तमंत्री ने उपरोक्त 1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज सहित 20.97 लाख

सामयिक वार्ता अंश
www.lohiatoday.com
पर भी पढ़ सकते हैं।

करोड़ रुपये के एक विस्तृत पैकेज की घोषणा की संक्षेप में इसका व्योरा इस तरह है। पहला अंश 5.94 लाख करोड़ रुपये का है और वह अंश नकदी की कमी से जुड़ते

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर केंद्रित है। इसमें इन उद्यमों की 45 लाख इकाइयों की बैंकों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के गारंटी मुक्त (कलेटल फ्री) ऋण सहित अन्य कई प्रकार के ऋणों का खुलासा किया गया है।

दूसरा अंश किसानों, श्रमिकों और अन्य पंचायत क्षेत्र की जरूरतों पर केंद्रित है। यह अंश 3 लाख 10 हजार करोड़ के बराबर है और यह मुख्यतः इस प्रकार आवंटित है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए छह करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ का रियायती उधार नाबार्ड के कार्यशील युंजी कोष में 30,000 करोड़ रुपये का इजाजत ताकि 3 करोड़ किसानों के लिए ज्यादा उधार की व्यवस्था की जा सके। छह लाख परिवारों द्वारा रियायती मकानों के लिए उधार पर ब्याज सब्सिडी के लिए 7000 करोड़ रुपये। प्रवासी श्रमिकों के लिए मुफ्त अनाज के लिए 3500 करोड़ रुपये। 50 लाख फेरीकलों में से प्रत्येक को कार्यशील युंजी के इस हजार रुपये की उधार राशि के लिए 5000 करोड़ के बराबर विशेष उधार सुविधा का प्रावधान।

तीसरा अंश 1.50 लाख करोड़ रुपये का है, जिसके अंतर्गत कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के लिए 1 लाख करोड़ रुपये। प्रधानमंत्री ग्राम संपदा योजना के लिए 20

हजार करोड़ रुपये, पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कोष के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है।

चौथा और पांचवां अंश मुख्यतः पुराने फैसलों और पुराने सुधारों को नई दिशा देने पर केंद्रित है। इन दोनों अंशों में कुल मिलाकर 48.100 करोड़ रुपये का प्रावधान है। जिनमें मुख्यतः मनोरा योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है।

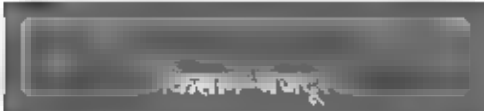
उपरोक्त पांच अंशों के अलावा गरीब कल्याण योजना और 12 मई से पहले रहता पर किए गए अन्य व्यय को भी पैकेज में जोड़ा गया है। इसके साथ रिजर्व

काराबार बंद होने पर भी कई तरह के स्थिर खर्च कारोबारियों को वहन करने पड़ते हैं। जैसे- किंगया, ब्याज, लाइसेंस फीस आदि। महामंदी का होटल, रेस्तरां, एयरलाइंस बस-टैक्सी ऑपरेटर, ट्रांसपोर्टर आदि पर बहुत ज्यादा असर हुआ है।



बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के कारण आठ लाख करोड़ के बराबर उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त तरलता (लिक्विडिटी) को भी इस पैकेज में जोड़ा गया है। इस तरह कुल मिलाकर, यह पैकेज 20.97 लाख करोड़ रुपये का है जो कि राष्ट्रीय आय के बकरीबन 10 फीसदी के बराबर है। काफी दिनों से (छाह पांच माह से) देश में महामंदी का दौर चल रहा है और इस कारण यह सवाल पैदा होता है कि क्या यह पैकेज देश की जरूरतों की कसौटी पर खरा उतरा है?

पैकेज कितना व्यापक है? उपरोक्त पैकेज के तीन हिस्से हैं। 1 राजकोषीय फिसकल (पैकेज), 2 बैंकों और गैर बैंकिंग वित्त निगम (एनबीएफएफ) द्वारा



प्रदत्त ऋण, 3 रिजर्व बैंक का तरलता लिक्विडिटी पैकेज

कुल पैकेज 20 97 लाख करोड़ रुपये का है और यह अगस्त माह तक के लिए था। जबकि राहत पर राजकोषीय व्यय को कुल राशि तकरीबन 3.14 लाख करोड़ रुपये आवंटित की गई है और इसमें नवंबर तक का अनुमानित व्यय भी जोड़ा गया है इस का खर्च इस तरह है।

— गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को नवंबर तक 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और इसके साथ छर महीने किलो दाल या घना भी। इसके तहत अप्रैल में 93% गेहूं में 91% और जून में 71% को अनाज दिया जा चुका है। इस योजना पर नवंबर तक का बजट 1.5 लाख करोड़ रुपय है।

25 62 करोड़ जन धन खाताधारक रिजर्वों की दो महीने की सहायता राशि पर 12,810 करोड़ रुपये खर्च आए थे। यानी इस मद का नवंबर तक का बजट 44 935 करोड़ रुपय है।

2 82 करोड़ वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगजनों पर दो महीने तक की सहायता राशि पर 1405 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। यानी इसका नवंबर तक का बजट 4918 करोड़ रुपये है

उच्चला योजना के अंतर्गत दो महीनों में 4 82 करोड़ गैस सिलेंडर बंटे गए थे यानी नवंबर तक का 12.05 करोड़ गैस सिलेंडर बंटे जाने हैं। तीन महीनों का बजट 13 500 करोड़ रुपये था यानी इसका नवंबर तक का बजट 31 500 करोड़ रुपये है।

निर्माण श्रमिकों के लिए 31,000 करोड़ रुपये की राशि है

— मनरेगा के अंतर्गत योजना पर 40,000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन भी किया गया है

हनु सबका जोड़ तकरीबन 3.14 लाख करोड़ रुपये है जो कि राष्ट्रीय आय के डेढ़ फीसदी के लगभग है और यह राशि जरूरत से बहुत कम है। इस असंतिवत से नीतिकार अनजान नहीं है। मौजूदा हालात

का जायज लेते हुए रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, खलात सुधारने और महमारी का मुकाबला करने में सक्षमरी खय में भारे इजाफा हो चुका है। इससे समाज मांग बढ़ाने के लिए सरकारी व्यय में और इजाफा करने की गुंजाईश नहीं है दूसरे जव्दों में सरकार के पास महमारी की गरीबों को बहुत सी बुनियादी जरूरतों का इंतजाम करने के लिए संसाधन नहीं हैं पर यह तर्क सही स्थिति व्यक्त नहीं करता है संसाधन जुटाए जा सकते हैं। पर यह उस्ता नक्कदतवाद के विपरीत है। इस विषय पर इस लेख के अगले हिस्से में तफसील से चर्चा की जायगी।

महामंदी का असर सेवा पर भी है। कई निजी स्कूलों के अध्यापकों को पिछले तीन-चार माह से वेतन नहीं मिला है। ये स्कूल स्व वित्त पोषित हैं और इनको इस दौरान फीस की अदायगी नहीं हुई है। कई स्कूल तो किराया आदि भी नहीं दे पा रहे हैं।

सप्लाई स्टिम्बुलस (आपूर्ति प्रोत्साहन) कारगर नहीं है : गौरतलब है कि राजकोषीय पैकेज को सबसे कम अहमियत दी गई थी। योजना और उत्पादन में क्कतरी के लिए नीतिकारों ने मौद्रिक नीति को चुन था इसके पैसाकारों की दलील इस तरह है बैंक ऋण और रिजर्व बैंक के द्वारा उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त तरलता (लिक्विडिटी) से साख प्रोत्साहन (क्रेडिट स्टिम्बुलस) की प्रक्रिया मजबूत होगी। इससे बड़ी मात्रा में वित्तीय पूंजी का सर्जन होगा, जिससे निजी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा भारी मात्रा में निवेश होगा। इस प्रक्रिया से आपूर्ति प्रोत्साहन के माध्यम से योजना और उत्पादन में बढ़ोतरी का दावा इस नीति में निहित था पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ

कार्यशील पूंजी के लिए तरलता जरूरतों के अनुसार बैंक उद्यमों में इजाफा हुआ है। पर उद्यमियों ने मौजूदा हालात में नए निवेश के लिए ऋणों को लेने से पूरी तरह गुरेज किया है इसके विपरीत कई कंपनियां बैंक ऋणों के खेड़ को कम करने के लिए भी राइट्स इश्यू पेश कर इनिवटी निवेश में इजाफा कर रही है इससे बैंक ऋणों की मांग में बहुत कमी आई है

महामारी से अनिश्चितता का माहौल पनप रहा है और इस कारण अनुस्ता का भाव बड़ रहा है। इसका एक परिणाम यह है कि अर्थव्यवस्था में नकदी का परिसंचरण (सर्कुलेशन, बढ़कर एक रिकॉर्ड स्तर पर आ गया है इसका बैंकों द्वारा जमा खातों पर नक्कदतक प्रभाव पड़ा है पर इस अस्मान्य माहौल में यह बैंकों के लिए एक राहत की ही बात है क्योंकि बैंक जमा खातों पर 4 से 6 फीसदी ब्याज देते हैं और उन्होंने इन दिनों लाखों करोड़ रुपयों की अप्रयुक्त रकम मात्र 3 35 फीसदी ब्याज दर पर रिजर्व बैंक के पास जमा कर रखी है। आम हालात में बैंक जमा खातों पर कपाह करते हैं और आज की परिस्थिति में वे नए जमा खातों की लागत को भरपाई भी नहीं कर पा रहे हैं

उधार के मामले में विश्वमनीयता के पात्र सुस्थापित करोखरी बैंक ऋणों में इजाफा करने में अनिच्छुक है। दूसरी ओर इस अनिश्चितता के माहौल में बैंक नए असायियों के उधार देने का जोरिखम लेने से कतर रहे हैं। कियेक और सावधानी के आधार पर यही वक्ता का तफाजा भी है आज बहुत बड़ी संख्या में कारेवार बंद हैं और अनिश्चितता का माहौल है सवाल ये सीधा और स्पष्ट है इन परिस्थितियों में आपूर्ति प्रोत्साहन कैसे पनप सकता था?

जरूरत किमांड स्टिम्बुलस की है महामंदी के शुरूआती दौर में ही कई विशेषज्ञों ने व्यापक राजकोषीय पैकेज के पक्ष में अपनी राय दी है। क्योंकि पारिस्मलियां स्पष्ट- तरलता जान (लिक्विडिटी ट्रेप) के अनुरूप है इसके लिए मांग प्रोत्साहन डिमांड स्टिम्बुलस)

की जरूरत है और यह जरूरत एक राजकोषीय (फिस्कल) पैकेज से ही पूरी की जा सकती है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में आर्थिक गतिविधियों में अचूतपूर्ण कमी आई है और खपत को तगड़ा झरका लगा है। इसके लिए बड़े राजकोषीय पैकेज की जरूरत तो है पर सरकारें खर्च बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है।

मौजूदा हालात में सरकारों राजस्व की स्थिति काफी पतली है। सरकारी राजस्व कम है और सरकारी व्यय ज्यादा है। वो बजटीय घाटे की स्थिति का सामना करना पड़ता है। बजटीय घाटा असाधारण नहीं है पर सवाल बजटीय घाटे को सीमाबद्ध करने से जुड़ा है। क्यबंदे-कानून का हवाला दिया जा रहा है। 2003 में 'फिस्कल रिस्क्सविजिलेंटी एंड अजट मैनेजमेंट ऐक्ट' पारित किया गया था। गौरतलब कि इस ऐक्ट की इन अपेक्षाओं को आज तक अमल में नहीं लाया गया है। 31 मार्च, 2008 तक राजस्व खाते के घाटे को खत्म करना होगा, जो कि अब तक नहीं हुए हैं। यानी बजटीय घाटे का इलेमाल पूंजीगत परिसंपत्तियों के सर्जन के लिए हो लेना चाहिए पर ऐसा नहीं हो रहा है। ऐक्ट का अपेक्षा की परखंडन करते हुए इन 17 वर्षों में सरकार के प्रशासनिक खर्चों को बढ़ोतरी पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया गया है। पर गरीबों-आवास के लिए संसाधन जुटाने में क्यबंदे-कानून की आइ ली जा रही है।

मुद्रास्फीति का जवाब आव-नीति है - सरकारी राजस्व का बड़ा हिस्सा करों से प्राप्त राजस्व पर आधारित है। भारत में अन्य देशों के मुकाबले करों का बोझ अमीरों पर कम और गरीबों पर ज्यादा है। भारत में सेवा एवं वस्तु करों (जीएसटी) की दरें 28 फीसदी तक हैं। जबकि बहुत से देशों में 15 फीसदी से कम हैं। दूसरी ओर भारत में आयकर की अधिकतम दर 30 फीसदी है और कई अन्य देशों में 50 फीसदी से ज्यादा है। यही नहीं, संपत्ति-कर को 2014 में हटा दिया गया था और एस्टेट शुल्क (उत्तराधिकार कर) को 1986 में हटा दिया गया था। जगह है कि आयकर की उच्चतम दर में बढ़ोतरी की जा सकती

है। संपत्ति कर और एस्टेट शुल्क को उठाया जा सकता है। इन नीतियों परिवर्तनों से सरकारी राजस्व में आवश्यकता के अनुसार इजाजत किया जा सकता है।

भारत में 1990 के पूर्व अर्थव्यवस्था की अभिकतम दर 50 फीसदी से ज्यादा थी पर विवादोद्धार लैफर वक्र पर आधारित दलील देकर इन्हें तेजी से घटाया जाता रहा है। लैफर वक्र के मुताबिक दर घटाने से राजस्व बढ़ता है। इसके पक्ष में अनुभवजन्य (इम्पिरिकल) साक्ष्य नहीं है। भारत में आयकर की दर घटाने से राजस्व घटा ही है जिसकी कमी को वस्तु करों को बढ़ाकर पूरा करने की असफल चेष्ट की

कारोबारी, वतनभोगी, व्यवसायी आदि सभी क्षेत्र महामारी से त्रस्त हैं। महामारी-जन्य जोखिमों से कैसे निवृत्ता जा सकता है, इनकी लागतों को कौन और कैसे सहन करेगा? इन नीतिगत सवालों पर स्पष्ट नीति अपनाकर उसे शीघ्र अमल में लाना जरूरी है।

जाती रही है। राजस्व की कमी के परिणामस्वरूप शिक्षा और चिकित्सा का निजीकरण करके सरकारों व्यव को घटाया गया है।

वैसे महामारी के पूर्व ही देश की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही थी और इसका कारण गैर-व्यापार सख्ति है। महामारी से समस्या अति बिगड़ गई है और इन दोनों समस्याओं का समाधान कल्याणकारी गतिविधियों के विस्तार में ही निहित है। मांग प्रोत्साहन के लिए सरकारी खर्चों को गुरंत बढ़ाना आवश्यक है। चाहे कि इसके लिए बजटीय घाटे का मुदीकरण किया जाए या सार्वजनिक ऋण लिया जाए। बैंक ऋणों की मांग इस वक्त संकुचित है और इसलिए सार्वजनिक ऋण जुटाना मुश्किल

नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्ष करों, आयकर आदि, में बढ़ोतरी करके अगले कुछ वर्षों में ही सार्वजनिक ऋण कम किए जा सकते हैं।

बजटीय घाटे में बढ़ोतरी से दायों में उछाल अर्थात् मुद्रास्फीति की समस्या आ सकती है। पर इस समस्या को काफी हद तक आय नीति से निबटा जा सकता है। वक्त का तकाजा आय नीति है। वर्तमान परिदृश्य में इस नीति का प्रमुख फलस्वरूप नकद राशि या जिस के जरिए जरूरतमंदों को आव का स्थानांतरण है। जनसाधारण के पास क्यशक्ति से मांग का तेजी से सृजन होने से रोजगार और उत्पादन में तेजी आएगी और महामंदी के दौर से देश को निजात मिलेगी। पिछले साल की आर्थिक सुस्ती (स्लोडउन) और मौजूदा महामारी के दौरान असफलताओं का कारण नवउदारवादी नीतियां हैं। कल्याणकारी नीतियों से ही देश बराबरी और समृद्धि की दिशा में बढ़ सकता है। इन नीतियों से मौजूदा परिस्थितियों में देश को गरीबों के सैलाब से निजात दिलाई जा सकती है।

आखिर सरकार कतार क्यों खी है?

आखिर में यह सवाल उठता है कि सरकार फिस्कल डिस्टिगुलस (राजकोषीय प्रोत्साहन) से कतार क्यों खी है? अन्य देशों के मुकाबले भारत हम मामले में अपवाद क्यों है? सरकार गरीबों और जरूरतमंदों की खुले हाथों से मदद क्यों नहीं कर रही है? यह दलील खोखली है कि सरकार संसाधन नहीं जुटा सकती है। क्योंकि राजकोषीय स्थिति काफी कमजोर है। भारत का सार्वजनिक ऋण राष्ट्रीय आय के 70 फीसदी है और शासकीय प्रतिभूतियों पर 6 फीसदी ब्याज है। इस तरह बजट पर इसका सालाना बोझ राष्ट्रीय आय के 4 फीसदी से ज्यादा है। कई देशों में यह 100 फीसदी से ज्यादा है पर ब्याज की दर 2 फीसदी से भी कम है। भारत में जो शासकीय प्रतिभूतियों का बाजार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में है। अतः यह बोझ घटाया जा सकता है। इस आपदा के वक्त भी सरकार लक्ष्य कदम उठाने से कतर क्यों रही है?

विशेष अंक

कॉरपोरेट खेती के लिए बदले जा रहे कानून

दिवेकानंद माशने

माख सहित पूरी दुनिया की लूट करने के लिए कॉरपोरेट कंपनियां खेती, उद्योग और व्यापार पर कब्जा करना चाहती हैं। भारत में इन कंपनियों ने योजनाबद्ध तरीके से प्रमोशन को खत्म किया जल्द जमीन खोज पर मालिकाना हक प्राप्त किया अब वह खेती और व्यापार पर कब्जा करना चाहते हैं भारत सरकार द्वारा जल जंगल जमीन खनिज आदि प्राकृतिक संसाधनों पर कॉरपोरेट को मालिकाना हक देने के लिए नीति और

**प्राकृतिक खेती को
रासायनिक खेती, थाली में
जहर, बीजों की स्वाधीनता,
फसलों की जैव विविधता
नष्ट कर एक फसली खेती में
बदलने के लिए अगर कोई
एक व्यक्ति सबसे अधिक
जिम्मेदार है तो वह एम. एस.
स्वामीनाथन जी है।**

कानूनों में बदलाव की प्रक्रिया जारी है बैंक, बीमा कंपनियां रेल और सभी सार्वजनिक क्षेत्रों को देशी-विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। अब सरकार खेती और व्यापार को कॉरपोरेट को सौंपने के लिए नीतियां और कानूनों में बदलाव कर रही है

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसानों की संख्या आधी करना और धीरे-धीरे खेती में केवल 20 प्रतिशत किसान रखकर बाकी किसानों को खेती से बाहर करना केंद्र सरकार और नीति आयोग को घोषित नीति है। यह 20 प्रतिशत किसान कॉरपोरेट किसान होंगे जो कंपनी खेती या करार खेती के माध्यम से खेती करेंगे सरकार मनती है कि छोटे जोत रखने वाले किसान पूंजा तंत्रज्ञान के अभाव के कारण अधिक उत्पादन की चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर पाते इसलिए उन्हें खेती से हटाना जरूरी है

दुनिया के कौन से देश में कौन से उत्पादन की कितनी जरूरत है, इसका अध्ययन कर डेटा इकट्ठा किया जाएगा और कॉरपोरेट खेती या करार खेती द्वारा दुनिया के बाजार के लिए अधिक मुनाफा देने वाली फसल पैदा की जाएगी। कंपनियों द्वारा गुणवत्ता मानक के आधार पर किसानों से ऑनलाइन फसलें खरीदी जाएगी एग्रीगेट गोदामों में ही भंडारण किया जाएगा। सब ही कृषि प्रक्रिया उद्योगों में

तैयार उत्पाद बनाए जाएंगे। खरीद और बिक्री के लिए सप्लाय चेन का नेटवर्क बनाकर कच्चा माल और प्रक्रिया उत्पाद दुनिया के बाजारों में मुनाफा कर्षे संभावना देखकर बेचे जाएंगे यह कंपनियां अत्यांत-निर्यात के माध्यम से फसलों के दाम बढ़ाने-घटाने का काम करेंगी

इसे एक उद्घरण से समझते हैं। किसानों की प्रांशुतर कंपनियों बनाने का काम तो पहले से चल रहा है। कंपनी करार खेती द्वारा किसी उत्पादक किसान के समूह के साथ एक करार करके आलू की पैदावार सुनिश्चित करेगी। सभी इन्पुट, तकनीकी और वित्तीय उपलब्ध करायेंगी। उत्पादन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किस कंपनी से कौन सा बीज, खाद, कीटनाशक का इस्तेमाल करना है वह सब कंपनियां तय करेंगी। गुणवत्ता के मानक पूरे करने पर ही आलू तय कीमत पर खरीदा जाएगा किसान अगर प्रशिधिर है तो खेती में प्रशुद्धी कर सकेगा। यह गुणवत्ता पूर्ण आलू या फिर आलू घिया या अन्य प्रक्रिया उत्पाद घरेलू या विदेशी बाजार में जहां अधिक मुनाफा मिलेगा वहां बेचा जाएगा।

मान लीजिए भारत में प्याज की पैदावार अच्छी हुई है। किसानों की बाजार में अच्छे दाम मिल रहे हैं। तब यह कंपनियां विदेशों से प्याज आयात करके बाजार में उतारेगी और प्याज की कीमतें गिर देंगी। फिर गिरी कीमतों से बड़े पैमाने में प्याज खरीद कर पीपीटी में बनाए गए गोदामों में जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम से हटने के कल्याण चाहे जितना भंडारण कर लेगी और दुनिया के बाजार में जहां जब अधिक मुनाफा मिलेगा वहां बेचेगी। यह तो आज भी होता है लेकिन अब उसे कानून बनाकर एक व्यवस्था का रूप दिया जा रहा है

किसानों के लिए तो आज की व्यवस्था ही लूट की व्यवस्था है। जिसने किसानों को बदहाल करके रखा है लेकिन अब इस लूट व्यवस्था की वैश्विक लूट व्यवस्था में बदलने और कानूनी दायरे में लाने के लिए बदलाव किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने करार खेती कानून जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम, कृषि उपज वाणिज्य एवं बाजार अध्यादेश बनाए गए हैं

कृषि के लिए बिजली की सार्वजनिक खतम करना, सिंचाई के लिए मीटर से नापकर पानी

की बिजली पैरोलियम पर सर्वोपरी शक्ति करना खेती में पूंजी निवेश की अनुमति देना इजरायल और दूसरे देशों से कृषि तकनीकों प्राप्त करना. करम खेती कानून खेती जमीन की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाला सीलिंग कानून हटाने की कोशिश. पीपीपी के तहत गोदामों का निर्माण कृषि उत्पादों के भंडारण की पर्याप्त हद तक कृषि बाजार खर्चिता का अस्थिरता समाप्त करने के लिए एक देश एक बाजार कानून. कृषि उपज खरीद और प्रक्रिया के लिए प्रोड्यूसर कंपनी कानून. किसानों से सीधे ऑनलाइन खाद के लिए इनाम कानून आदि में कॉर्पोरेट खेती को लाभ पहुंचाने के लिए नीति और कानून में बदलाव की प्रक्रिया जारी है।

कंपनियों ने अपने उत्पाद बेचने के लिए व्यवस्था स्थापित कर ली है। कंपनी से ग्रहकों तक सप्लाइ चेन ई- बाजार, ई- कॉमर्स ई मार्केटिंग आदि के द्वारा उत्पाद पहुंचाया जाएगा. मॉल्स, शॉपिंग सेंटर, स्टिल दुकानें आदि में कंपनियां लगाना विस्तार का रस्ते है इसके लिए हर क्षेत्र में खरीद विक्री दोनों के लिए सप्लाइ चेन तैयार की जा रही है। भारत के लघु उद्यमी और छोटे व्यापारी केवल कमीशन एजेंट या फ्रैंचाइजी के रूप में काम करेंगे

भारत सरकार द्वारा नीति और कानूनों में किए जा रहे बदलाव को एक साथ जोड़कर देखने से नए भारत की भावी तस्वीर स्पष्ट होती है अब हम आसानी से समझ सकते हैं कि सरकार स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के लिए नहीं बल्कि खेती का कॉर्पोरेट के हजाले कारन के लिए कानून बना रही है लेकिन जैसे राशय नयी योजना पर अमल लिख देने से राशय अमृत

नहीं बन जाती जैसे ही कॉर्पोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए नीतियां बनकर उसे स्वदेशी और आत्मनिर्भरता कह देने से देश आत्मनिर्भर नहीं बनता. मेक इन इंडिया और परनिर्भरता को स्वदेशी और आत्मनिर्भर कहना केवल झूठ ही नहीं बल्कि यह देश के किसान, लघु उद्यमियों और छोटे व्यापारियों के साथ किया जा रहा धोखा है

जब किसानों के सामने इतनी बड़ी चुनौती हो, तब कुछ किसान संगठन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग कर देश के किसानों को पुनरुत्थ करने का काम कर रहे हैं. कर्ज माफी से किसानों को कुछ लाभ जरूर है लेकिन इस मांग का महत्व तभी है जब किसानों को कर्ज के जाल से स्वस्थ पुनर्नि के लिए प्रयास किए जाएं. अन्यथा कर्ज माफी किसानों को कम साहूकार बैंकों को ज्यादा मददगार शक्ति होती है. एमएसपी फसलों का उत्पादन मूल्य नहीं है बल्कि वह किसानों को न्यूनतम मूल्य की गारंटी देने के लिए बनाई गई व्यवस्था है. एमएसपी के तहत कुल उत्पादन के 10 प्रतिशत से कम फसलें खरीद की जाती है. अगर सी2 पर 50 प्रतिशत ह्रास बढ़ा दिए जाते है तब भी किसान की आब में केवल 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी

प्राकृतिक खेती को रसायनिक खेती में बदलने में थारो में जहर पहुंचाने में बीजों की स्वाधीनता. फसलों की जैव विविधता नष्ट

सामयिक चर्चा अब
www.lohiatoday.com
पर भी पढ़ सकते हैं।



कर एक फसली खेती में बदलने के लिए आम कोर एक व्यक्ति सबसे अधिक जिम्मेदार है तो वह एम एस स्वामीनाथन जी है। इसके बावजूद स्वामीनाथन आयोग लागू करो की मांग बेड़्यानी है।

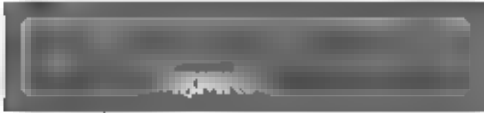
खेती को रसायन मुक्त और वाली को जहर मुक्त करना जरूरी है। विपश्चित खाद्यान्न की बढ़ती मांग को लाभ में परिमार्जित करने के लिए अब कॉर्पोरेट कंपनियों ने जैविक खेती और प्राकृतिक खेती करना शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार और कॉर्पोरेट कंपनियों ने मिलकर योजना बना ली है

केंद्र सरकार ने भारत की पांच ट्रिलियन (पचास लाख) डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये

**खरीद और बिक्री के लिए
सप्लाइ चेन का नेटवर्क
बनाकर कच्चा माल और
प्रक्रिया उत्पाद दुनिया के
बाजारों में मुनाफे की
समाधान देखकर खेती
जाएंगे। सबकुछ कॉर्पोरेट
के हाथों में चला जाएगा,
किसान गुलामी करेगा।**

के हिसाब से हर साल 20 लाख करोड़ रुपये निर्यात करने की योजना की थी। इस साल सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रूपयों में लगभग 80 प्रतिशत प्रति कर्ज की व्यवस्था है। यह बैंकों की साहूकारी की व्यवस्था है इसे आप विदेशी बैंकों की निवेश अनुमति से जोड़कर देखेंगे तब तस्वीर और साफ होगी।

अभी भी भारत की स्थिति बहुत विकट है लेकिन वर्तमान सरकार ने नीतियां अपना रही है. उससे हम कॉर्पोरेटी गुलामी से नहीं बच सकते हैं। उससे देश पूरी तरह से कॉर्पोरेटी गुलामी में जकड़ जाएगा. हम अंग्रेजों के डेड़ से सलत गुलाम रहे, लेकिन अगर हम कॉर्पोरेटी गुलामी में जकड़ गए तो हजारों साल तक इस गुलामी से मुक्त होना संभव नहीं है। ■



भारत भूषण चौधरी

मानव सभ्यता के इतिहास में कोरोना से उत्पन्न बर्तमान संकट अभूतपूर्व है इस महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। कोई भी देश अछूता नहीं यह वैश्वीकरण का प्रभाव है इसलिए भी क्योंकि दुनिया के सभी देश एक-दूसरे से व्यापार, आवाजाही और सांस्कृतिक तौर पर नजदीकी से जुड़े हुए हैं। कोविड- 19 अब तक के पाए गए वायरसों में सबसे ज्यादा तेजी से फैलाने वाला विषाणु है और बड़ी संख्या में दूसरों को संक्रमित करता है। इसका संक्रमण एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ही फैलता है। अब तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार वह वायरस चीन के चुआन शहर में समुदाय से मनुष्य में आया और फिर फैलता ही गया। जिन राष्ट्रों देशों में चुआन से ज्यादा आवागमन था, वहां यह पहले फैला और आज आठ महीने बाद विश्व के सभी 213 देशों में गॉय-गॉय तक फैल चुका है।

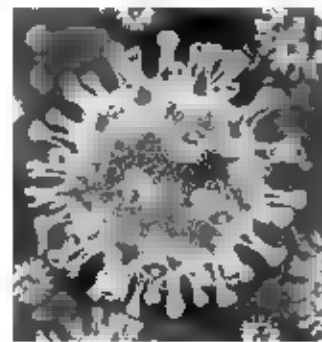
प्राथमिक चैर होने के कारण इस बीमारी का टीका वा इलाज अभी तक नहीं है। जनवरी 2021 से पहले आने के आसार भी नहीं हैं। तब तक सावधानी और न्याय ही उपाय है। कोविड- 19 के 80% संक्रमितों में कोई लक्षण नहीं सीधे फलतः ये दूसरों को बिना जानकारी संक्रमित करते रहते हैं। यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जांच कर संक्रामकों की अलग-थलग रखने पर जोर दिया जाता है। इससे संक्रमण समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन एक समय में कम लोग संक्रमित रहेंगे जिनकी देखभाल और इलाज हमारे सीमित संसाधनों में भी संभव हो पाएगा। साथ ही ज्यादा संख्या में लोग अपनी रोजमर्रा के काम-काज कर पाएंगे अर्थव्यवस्था धीमी गति से ही सही, लेकिन चालती रहेगी। लेकिन हमारे देश में अभी तक इसके ऊपर किया गया जांच की रफ्तार न्यूनतम रही साथ ही फटेदार लॉकडाउन लगाया गया परिणामतः छह महीने बाद भी संक्रमण बढ़त पर ही है, बेरोजगारी चारम पर और अर्थव्यवस्था चक्रनाचूर हो गई।

भारत के संदर्भ में यह ध्यान में रखा जाना आवश्यक है कि यहाँ 80% लोग गरीब हैं। भीड़-भाड़ वाली जगहों में रहने काम करते और यात्रा करते हैं। इनके संक्रमित होने की

कोविड-19 महामारी के प्रभाव और आगे की राह

संभावना संप्रांत लोगों से कई गुना ज्यादा है कोविड- 19 से संक्रमित व्यक्ति के जीवनप्रद अंग (वाइटल ऑर्गंस) प्रभावित होते हैं जिनका इलाज संरक्षण और गहन मेडिकल देखरेख समय रहते हुए न किया जाए तो मरीज की मौत भी हो सकती है। इस संक्रमण से प्रभावित मरीजों में (अभी तक के प्राप्त आँकड़ों के अनुसार) मौत की संभावना 2% से 15% के बीच है।

क्या यह स्थिति एक वैश्व प्रकोप की तरह है जिसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था? जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, न्यूजीलैंड, जर्मनी जैसे कई देश हैं जिनोंने



थोड़े नुकसान में ही और कम समय में इस महामारी पर काबू पाया और अपने कामों पर वापस आ गए। लेकिन आज छह महीने गुजर जाने के बाद भी भारत में संक्रमण और मौतें बढ़त पर हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, अब तक के आँकड़े बढ़ते ही जाएंगे। ऐसा क्यों? क्या अभी जिस तरह हमारा देश महामारी और उससे उपजी समस्याओं के निवारण का प्रयास कर रहा है वे सही और कारगर हैं?

दुर्लभ देशों के अनुभव खनने होने के बावजूद खतरे को न भांपना, विदेश से आने वाले यात्रियों की सघन जांच न करना, उन पर

पाबंदी न लगाना, संक्रमण फैल जाने के बाद भी 'नमस्ते ट्रंप' और बाध्य प्रदेश सरकार गिराने में व्यस्तता आदि के कारण संक्रमण देश के हर भाग में खेवहास फैलता रहा। कोरोना संकट को तबलीमियों के जिम्मे लगाते रहना मौजूदा दुस्मरानों के राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ति तो करता रहा लेकिन संक्रमण की रोकथाम पर इनका धिरीत असर हुआ। जांच, पीपीई किट्स और आस्पनालों, बिस्तरों आदि के इंतजाम को तबज्जो न देना, गलत समय पर कुर तरीके से बिना समय दिए, प्रवासी मजदूरों के खाने-रहने की व्यवस्था बिना किए। लॉकडाउन लगा देना ये सब ऐसे बिना सोचे समझे किए गए कृत्य थे जिनसे करोड़ों कामगारों के अस्तित्व का संकट पैदा हो गया। उनके लाखों की संख्या में बिना जांच कई रायों से होते हुए घर वापस

सामयिक पार्श्व अब
www.lohitoday.com
पर भी पढ़ सकते हैं।

अपने से कोरांग गांव गांव तक फैल गया। ये केंद्र सरकार के अधिनायक वादी प्रवृत्ति और विशेषज्ञों की सलाह के बिना निर्णय लेने का आदत के कारण हुआ।

अगर हम अपने देश के कोंग्रस पर नियंत्रण के प्रयासों को नियतनाम दक्षिण कोरिया, जर्मनी वा चीन जैसे देशों से तुलना करें तो पाएंगे कि हमारे यहाँ अत्यधिक संक्रमण सबसे लंबी अवधि तक जारी है। हमारी रणनीति में पुलिस-खल पर जरूरी से ज्यादा निर्भरता रही है। वहीं जिन मुस्को ने बेहतर प्रदर्शन किया वहाँ विशेषज्ञों की सलाह, नागरिकों को भागीदारी, जनता को पुरा विश्वास में रखना अत्याहो कर फैलाने न देना तकनीक का अधिक और बेहतर इस्तेमाल और लगातार जानकारी के आदान प्रदान को तबज्जो दो गई।

महामारी

हम तानी थाली दिया पणववा जैसे टाटकों में समय और संसाधन बसावकर रहे। पारदर्शी तरीके से पैस कांफ्रेंस कर समस्या से संबंधित सभी जानकारी को से जनता को अवगत कराना जो हमारे देश में आम होता ही नहीं। हमारे प्रधानमंत्री तो कभी प्रेस बातों करते हैं नहीं।

पिछले दो दशकों में स्वास्थ्य और अनुसंधान के क्षेत्रों की इतनी उपेक्षा की गई है कि कोरोना वैश्वी विपरीतता का सामना करने के लिए हमारे पास विशेषज्ञता का अभाव और वैज्ञानिक संस्थाओं में ताल-मेल की कमी का सामना करना पड़े देश को भुगतना पड़ रहा है। शुरुआत में केंद्र सरकार द्वारा रोज बुखाने की फायदा जारी करते रहना और बाद में स्थिति अनियंत्रित हो जाने पर खुपसी साथ लेना, किसी जनतांत्रिक सरकार के कर्तव्य त्वर का अकल्प उदाहरण होगा। आज भी जब हम रोज के संक्रमण और मौत के आंकड़ों में लगातार सभी देशों से आगे हैं, जांच की संख्या कई गुना कम है। सरकार का प्रयास वह दिखाने का है कि हम सबसे बेहतर उपाय कर रहे हैं, दूसरे देशों के लिए उदाहरण पैस कर रहे हैं, जो एक विरल स्तर का झूठ है। शासक दल के एक अत्यंत करीबी सहयोगी ने तो बिना वैज्ञानिक प्रमाण के कोरोना का इलाज की दवा भी बेच दी। कोरोना से बचाव के लिए एक केंद्रीय मंत्री पापट का प्रचार कर रहे थे जो अब खुद कोरोना के शिकार हो गए हैं। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि हमारे क्विंट स्वास्थ्य कर्मियों को अंचल अकरण, समय पर वेतन व सुविधाएं नहीं दी जा रही उनके साथ दुर्व्यवहार की तबाल घटनाएं हो रही हैं। क्विंट मरीजों से सहानुभूति रखने की जगह उनका निरस्कार किया जा रहा है यह हमारे समाज की संवेदनहीनता को अजागर करता है।

कोविड-19 की महामारी ने हमारे देश में जहां एक तरफ लाखों लोगों को बीमार किया, 60,000 से भी अधिक लोगों की जान ली, वहीं कई और भी गंभीर समस्याएं पैदा कर दीं। मसलन करडों का संख्या में नौकरा, मजदूरों के अत्यंत खराब जाल कृपावण और संबंधित लोगों का घटना अर्थव्यवस्था का घटती से उतर जाना, परेण्ड्रिस्ता, लुटपाट, बच्चों को तस्करी, चोरी, आदि में वृद्धि प्रमुख हैं। आर्थिक, सामाजिक कामों से और अकेलेपन से जनसंख्या के बड़े हिस्से में

मानांसक तनाव बेहद बढ़ा है। आत्महत्याओं के मामले बढ़े हैं। अस्पताल ओपेडी क्लिनिक्स आदि के बंदप्राय रहने से सामाजिक रोगियों का इलाज नहीं हो पाया जो असाध्य रोग में परित्त हो गए। कैंसर, गुर्दे दिल आदि के कई गंभीर रोगियों को समय पर अस्पताल में जाह नहीं मिलने से जानें भी चली गईं। नैकाकरण कार्यक्रम में बाधा के कारण जो बच्चे छुट जाएंगे उनके असाध्य रोगों से पीड़ित होने का खतरा भी बढ़ा है।

गतगतिक गतिविधियों पर रोक लगने और भटलने में काम-काज नहीं होने के कारण मानवधिकारों के हनन की घटनाओं में वृद्धि हुई है। राज्या सरकार मीके का

भास्त के संदर्भ में यह ध्यान में रखा जाना आवश्यक है कि यहां 80% लोग गरीब हैं। भीड़-भाड़ वाली जगहों में रहने/ काम करते और यात्रा करते हैं। उनके संक्रमित होने की संभावना संभांत लोगों से कई गुना ज्यादा है।

फावत उत्तरकर अपने विरोधियों बुद्धिजीवियों अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है। उन्हें यूएपीए, एनएसए, राजदौह जैसे कूर कमूनों के तहत जेलों में बंद कर रही है। नागरिकों को जमानत नहीं मिल रही। श्रमिक विरोधी कानून लागू कर दिए गए हैं। राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता अपना विरोध तक रही दर्ज कर सकते जेलों में बंद विचारधीन कैदी बड़ी संख्या में कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं।

इस महासंकट को विभिन्न दलों ने जिन तरीकों से हल करने की कोशिश की, और उनके जो नतीजे अभी तक सामने आए हैं। उनसे सीख मिलनी है कि वैज्ञानिक घटनाओं को जमला आयोजनों सामाजिक द्वेष आदि हथकंडों से छुटलाया नहीं जा सकता। महामारी जैसी समस्याओं का समाधान अहंकार,

आत्ममृग्यता मज्जम और चकाचौंध जगाने से नहीं होता। चार्निक नमीनो स्तर पर संज्ञेदगी से सभी को विश्वास में लेना अत्यधिक संसाधन और कमियों को लताका पोजनान्ठ तरीके से ही इनका हल किया जा सकता है।

ऐसे माहौल में जनता के बीच की विश्वसनीयता अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। नाकि सरकारी तंत्र की ओर से दिए गए निर्देशों पर लोग पूरे तरह विश्वास करें और उसका अनुकरण करें। पोंछे जल अशोय-सेतु के इस्तेमाल को बात चली हो जनता ने इसे शक की निगाह से देखा। कई स्थलों पर स्वस्थकर्मों जब मुहल्ले में नम्ने आदि लेने गए तो उन पर हल्ला किया गया। महामारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) जो अभी मृतप्राय संस्था है, उसे सशक्त व्यवस्था, बेसेवर एवं स्वायत्त बनाया जाए। अमेरिका की संस्था, सेंटर फॉर डिजिन कंट्रोल (सीडीसी) ने कई संक्रमण बाल रोगों को रोकथाम में उल्लेखनाय काम किया है। हालांकि इस संस्था के अमेरिका में होते हुए भी ट्रेष जैसे आत्ममृग्य और अहंकारी नेता ने उस काय नहीं करने दिया जिसका नतीजा सामने है। जन स्वास्थ्य, सामाजिक सुख, स्कुली शिक्षा, गरीबी उन्मूलन का कोई भी कार्यक्रम तभी सफल होता है जब उसे आर्थिक और प्रसाशनिक रूप से सशक्त विकेन्द्रीकृत शासन संस्थाओं द्वारा परिचालित किया जाए जैसे जिला पंचिद, ग्राम पंचायत, मगर निकाय नगर पंचायत वगैरह। कोरोना महामारी में सभी सफल देशों में भी ये संस्थाएं दक्षकों से सक्रिय रखी गई हैं। इसीलिए अभी इस कार्यक्रम में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। वहाँ के प्युनिमिल कांफ्रेंशन और कोउटी प्रशसन वगैरह। भारत में इन संस्थाओं को पूरा लोकतांत्रिक, सशक्त और सक्रिय बनाया ही नहीं गया है। नवीनतन महामारी प्रबंधन अधकचरे हंग से हो रहा है।

हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की घोषण कमी है। इस मद में हम अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का मात्र 1.3% खर्च करते हैं जबकि बाकी देश 7% से 12% तक। नवीनतन पूरे देश में जांच (जो भी हुआ) सिर्फ बड़े शहरों में ही, मरीजों का परीक्षण, सिद्धिओं को अलग रखने और उनके इलाज में हम समय से सक्षम नहीं हो पाए।

आजादी के आंदोलन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का योगदान

दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर (अब सेवानिवृत्त) रहे राजकुमार जैन समाजवादी आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्वों में से रहे हैं। वे बचपन से ही इस आंदोलन से जुड़े और जनक आंदोलन और संघर्षों से बहुत-बहुतकर हिस्सा लिया। हमने समाजवादी नेताओं और आंदोलन को लेकर खल रहे अन्ग्रेज प्रशासकों से खिल होकर उन्होंने नए माथियों के लिए समाजवादी आंदोलन की पूरी परंपरा को साधने रखने का संकल्प लिया है। इसी के तहत उन्होंने समाजवादी आंदोलन की पूरी परंपरा को लिपिबद्ध किया है। हम इसे लेखकाल के रूप में प्रकाशित करेंगे। प्रस्तुत है इसका पहला भाग।

राजकुमार जैन

आरत को रोकदों खल को अंग्रेजी गुलामी से मुक्ति महात्मा गांधी की कहनाई में अखिल भारतीय कांग्रेस के छोड़े तले हुए संघर्ष से मिली। सिंदूरान के सभी समाजवादी नेता और कार्यकर्ता महात्मा गांधी को अपना नेता तथा कांग्रेस को अपनी पार्टी मानते थे। फिर क्यों समाजवादियों ने कांग्रेस में रहते हुए अलग से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई, इसके बड़ा कारण थे? हमको जानना बंदत करूँ है।

आजादी की लड़ाई में समाजवादियों को दोहरी भूमिका थी। संघर्ष करने वाला सहने लंबे लंबे कारवास को भोगने का कार्य तो इनके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया तब, परंतु दूसरा काम जो समाजवादियों ने यह किया कि वे आजादी के साथ-साथ आर्थिक, सामाजिक स्वतंत्रता पर किसी नीति और सिद्धांत बने जिससे शोषण मुक्त समाजवादी समाज की रचना हो, वह दर्शन भी कांग्रेस में उठाते रहे समाजवादियों ने राष्ट्रीय संघर्ष को प्राथमिकता तथा उसमें कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार किया। साथ ही सामाजिक आर्थिक वैचारिक दबाव बनाकर कांग्रेस को एक समाजवादी संगठन के रूप में संरक्षित बनाने तथा स्वतंत्रता संग्राम का आधार व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से। पटना में 1934 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन से पूर्व ही कई प्रांतों में सोशलिस्ट समूह बनें वन नुक रं 933 में पंजाब में पंजाब सोशलिस्ट पार्टी बन ग।

मई 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनी 1933 में बनई खुने में सोशलिस्ट गुप बना बड़ीत गुजरात में फरवरी 1934 में गुप बन चुका था। मार्च 1934 में बनारस में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, इसी बीच उड़ीसा में भी सोशलिस्ट गुप बन गया।

आजादी के संघर्ष में महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, आदरताह खीं, सुभाषचंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल के साथ-साथ अन्धकार नरेन्द्र देव अग्रप्रकाश नारायण, डॉ रामचन्द्र लोहिया अत्युत पटवर्धन मुसुफ मेहर अली इत्यादि समाजवादी नेता भी पूर्ण तत्कत से उठे थे। गुलामी की जंजीर तोड़कर अंग्रेजी राज से मुक्ति महात्मा गांधी और कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य था कांग्रेस के अंदर और बाहर कई ऐसे ताकत थे जो समाजवादियों पर आरोप लगाते थे कि आजादी के मार्ग में वे बाधक बन रहे हैं क्योंकि इनकी नीतियों के कारण कांग्रेस के आंदोलन में शायक राजा महाराजा, जमींदार जागीरदार, स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा बलने लोष आंदोलन से छिटक जाएं। इन शंकाओं और सखलों का जवाब देते हुए कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पटना अधिवेशन में 7 मई 1934 को पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष आचार्य नरेन्द्र देव ने कहा था 'हम एक ऐसे समय में बिल रहे हैं जब हमारा राष्ट्रीय संगठन (कांग्रेस), एक संकट से गुजर रहा है। दुर्गामी महत्व के सवाल पर बिचार करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को बैठक कल हने जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि इस सम्मेलन में हम यह निर्णय करें कि इस महान

सभा को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में इमामत बसा योगदान होगा। राष्ट्रवादी आंदोलन को समाजवाद की दिशा की ओर मोड़ने की कोशिश करने पर हमें तुरंत इस अलोक्यता का विस्तार लेना पड़ता है कि राष्ट्रवाद और समाजवाद को मिलाकर कठिन है। अगर अपने देश में हम समाजवाद स्थापित करना चाहते हैं तो हम कांग्रेस के बाहर अपना एक स्वतंत्र गुप क्यों नहीं बना लेते? उसकी नीति से भवतंत्र होकर काम क्यों नहीं करते और साथ ही निम्नमध्यमवर्गीय वर्गों संघटन के प्रतिस्पर्धावादी प्रभावों से अपने कां पृक्त क्यों नहीं कर लेते? इसका उत्तर यह है कि हम अपने को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ चलने वाले महान राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करना नहीं चाहते और कांग्रेस आज उड़ी का प्रतीक है। हम यह स्पष्टका करते हैं कि कांग्रेस में आज कामकां और खसबियां हैं। फिर भी वह देश में आसानी से सबसे बड़ी क्रांतिकारी शक्ति बन सकती है। इसे यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय संघर्ष का वर्तमान चरण युर्गुआ लोकतांत्रिक क्रांति का है। अतः राष्ट्रीय आंदोलन से अपने को अलग कर लेना आपत्तको नीति होगी निःसंदेह कांग्रेस उस राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती है।

एक और सवाल है कांग्रेस से हमारा विश्वास का यह कोई मुश्किल मामला नहीं है और आसानी से सुलझाया जा सकता है। पहले बात तो यह है कि हमारा संगठन कांग्रेस पार्टी के भीतर है। वही बात बड़ी सीमा तक हमारे विश्वास की व्याख्या कर देती है। हम कांग्रेस के विरुद्ध हैं उसके विरोध या उसके प्रति आक्रामकता का प्रश्न ही नहीं है। एक पार्टी का तौर पर हमें कांग्रेस की हस्तचाली में उन्हें अपना ही सम्पत्ति हुए भाग लेना है। उन मुद्दों को छोड़कर, जिन पर कांग्रेस को किसी निश्चित नीति से हम असहमत हैं। साथ ही एक अल्पसंख्यक समूह के तौर कांग्रेस के भीतर अपने विचारों के प्रचार का हमें अधिकार है तथा अपनी नीति एवं दिशा पर चलते हुए, हमें कांग्रेस की जो नीतियां जनहितकारी न लगे, उनकी समीक्षा और विरोध तक करना चाहिए।

हमारे यह मानने के बावजूद कि वर्तमान भारतीय परिस्थिति में दोनों क्रांतिकारी का साथ साथ लाने की संभावना है। एक गुलाम देश के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता समाजवाद के रहने में एक पड़ाव है। लेकिन इन मामलों में कोई



इतिहासनाम

निश्चयन नहीं हो सकने लहान कुर मननना आंदोलन के नेतृत्व के गुणो पर निर्भर करेगा अगर नेतृत्व समाजवादी सिद्धांतों से लैस, राजनीतिक दूरदर्शित से संपन्न और साहस से काम कर सके और स्थितियां अनुकूल हों तो वह निश्चित तौर पर इससे फायदा उठाएगा।

कांग्रेस के अंदर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठन तथा आजादी के संघर्ष के साथ, समाजवादी विचारों को शोषक आजादी की लड़ाई को कमजोर करने के आरोप का जबाब देते हुए डी. रामबहादुर लोहिया ने 5 दिसंबर 1936 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण में कहा

हमसे सवाल किया जा सकता है कि तुम समाजवादी दल क्यों बनाए बैठे हो। जब तुम्हारा तात्कालिक लक्ष्य स्वतंत्रता-विरोध अंग्रेज राज से मुक्ति है तो तुम कांग्रेस के अतिरिक्त एक समाजवादी दल क्यों बनाए हो? इसका सही-सही उत्तर तो यही है कि हमारा दूसरा लक्ष्य, चाहे वह इतना तात्कालिक न हो, समाजवाद है लेकिन यह संपूर्ण उत्तर न होगा। हमारा समाजवादी दल इसलिए भी है कि हम समाजवाद के जरिए इतिहास के परिवर्तन के नियमों को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। सभी प्रगतिशील लड़ाइयों में बहुकर हाथ बंटा सकते हैं और फलतः स्वतंत्रता-संग्राम को भी ज्यादा अच्छी तरह चला सकते हैं इसलिए जब हम आजकल अक्सर यह अपदेश सुनते हैं कि समाजवादियों को पहने स्वायत्त का घुमन हल करना चाहिए, फिर बात में वे समाजवाद को बाँटें क्यों तो हमें इस अपदेश के बहुकषण पर इसी आती है हममें किसने कब और कहा कहा है कि राष्ट्रीय आजादी के पहले ही हम समाजवादी आजादी हासिल करने का छेसाता रखते हैं हमने तो साफ-साफ कहा है कि राष्ट्रीय आजादी ही हमारा तात्कालिक लक्ष्य है फिर भी हमें यह अपदेश क्यों दिया जाता है?

17 मई 1934 को ही क्यों पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका भी एक विशेष कारण था क्योंकि अगले दिन ही पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हो रहा था। तात्कालिक केंद्र में यह तह की विधायकता के लगे थे एक पूर्ण समाजवादी सोच का था, जो 1930-1939 के सिविल नाकाबानी तथा मोलमेज कांग्रेस की गलायी के कारण उज्जी निगल को बाँटकर तत्काल आजादी के लिए संघर्ष करने पर तैयार था। इस

सोच के अधिकतर बुलक अंग्रेजी हुकूमत से किसी प्रकार के समझौते के विरोध में थे। वे नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों द्वारा सुधारों के नाम पर होने वाले असंकीर्ण चुनावों में भग लिया जाए दूसरा तबका स्वराज पार्टी का था, जो कि अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग करने का हिमायती था वे संवैधानिक एवं सुधारवादी थे इनके सदस्य संघर्ष में विश्वास नहीं करते थे वे केवल विधायिका में प्रवेश के इच्छुक थे स्वराजवादियों में अधिकतर बड़े भूस्वामी राजाड़े उच्च स्तर का जीवन जीने वाले उदारवादी मजदूर-किसान विरोधी थे। एक तर्फ उनकी स्वराज पार्टी भी थी और दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर भी वे शामिल थे। गांधी जी का समर्थन भी इनसे मिल गया था। पटना में होने वाले कांग्रेस सम्मेलन में स्वराजवादी कारगिल प्रवेश का प्रस्ताव पास करने के लिए अतुर थे। नवगठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस अधिवेशन में एक वैकल्पिक प्रस्ताव पेश करते निर्णय लिया जो इस प्रकार था

वैकल्पिक प्रस्ताव करवा कांग्रेस में पारित मूल-अधिकांश वाले प्रस्ताव की प्रस्तापन घोषित करती है कि आम लोगों के शोषण की समाप्ति के लिए गहनतम स्वतंत्रता में करवाँ भूखी परिदृष्टि नती कस्विक आर्थिक स्वतंत्रता अवश्य शामिल होनी चाहिए। स्वतंत्रता संघर्ष का आधार विस्तृत करने और स्वराज्य प्राप्ति के बाद भी आम लोग आर्थिक शोषण के शिकार न बने रहें- इसे पक्का करने के लिए कांग्रेस को एक ऐसा कार्यक्रम अपनाया चाहिए जो कम और उद्देश्य में समाजवादी हो इसीलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कांग्रेस से सिफारिश करती है कि वह घोषित करें कि उसका उद्देश्य समाजवादी राज्य की स्थापना है और सत्ता पर कब्जा करने के बाद वह निम्नलिखित राजनैतिक समाजिक एवं आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर भारतीय राज्य के लिए संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा आहूत करेगी, जो सार्वभौम जालिब यताधिकतर (उन्हें स्थाधिकार नहीं होगा जिन्होंने स्वतंत्रता-संघर्ष का विरोध किया है। इसमें प्रतिनिधित्व कार्यात्मक आधार पर दिया जाएगा) के अभाव पर निर्वाचित हो, सभी एजितों का अत्यंत जनता को हस्तंतरित सं देश के आर्थिक जीवन का विकास राज्य द्वारा नियोजित एवं निर्मित हो, उत्पादन, वितरण एवं वितरण के

सभी संघर्षों के उत्तरोत्तर समाजीकरण के उद्देश्य से इस्मान, कपड़ा, जूट, रेलवे, लहजजतन खदान, बैंक एवं सार्वजनिक उपसंगिता जैसे प्रमुख एवं आधारभूत उद्योगों का समाजीकरण किया जाएगा, विदेश-व्यापार पर राज्य का एकधिकार होगा, ऐसे क्षेत्रों, जिनमें समाजीकरण नहीं हुआ है, में उत्पादन, वितरण एवं साख का राज्य द्वारा विनियमन होगा राजाओं जमींदारों एवं अन्य सभ्य शोषक-वर्गों का खाली किसानों के बीच भूमि का पुनर्वितरण किया जाएगा देश में पूरी कृषि के अंतोणात्वा सामुहिककरण के विचार से सहकारी एवं सामुहिक खेती को राज्य द्वारा प्रोत्साहन दिया जाएगा, किसानों एवं मजदूरों पर बकाया प्रणों की भाषी होगी

अखिल भारतीय कमेटी सिफारिश करती है कि जन आंदोलन पैदा करने का एकमात्र कारण तरीका आम लोगों को उनके आर्थिक हित के आधार पर संगठित करना है। कांग्रेस जन किसान एवं मजदूर संघों का संगठन करें और जहाँ ऐसे संघ अस्तित्व में हैं वहाँ आम लोगों के दैनंदिन संघर्षों में हिस्सा लेने और आगे उन्हें अग्रिम लक्ष्य तक ले जाने में नेतृत्व करने के विचार से उनमें प्रवेश करें।

इस प्रस्ताव के साथ एक अन्य प्रस्ताव कोसिल प्रवेश से संबंधित पेश किया गया, जिसमें सारांश कौंसिल प्रवेश का समर्थन था। इनमें था कि कार्यक्रम को कांग्रेस के खुल अधिवेशन में स्वीकृत किया जाए न कि कुछ लोगों द्वारा पास कर लिया जाए संसदीय गतिविधि कांग्रेस के निर्देशानुसार तथा नियंत्रण में हो न कि किसी स्वशासी संस्था के हथ में और कार्यक्रम पूर्ण रूप से समाजवादी विचार से भरा हो

कांग्रेस कार्यकारिणी में जयप्रकाश नावण ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा आचार्य नेन्द्र देव ने इसका समर्थन किया। समाजवादियों के संगठन के समर्थन में 35 मत तथा उसके विरोध में 86 मत पड़े इसलिए संगोधान अस्वीकृत हो गया।

समाजवादियों का वैकल्पिक प्रस्ताव गिर जरूर गया, परंतु इसके राजनीतिक ब्रभाव दूरगामी पड़े, क्योंकि पहली बार कांग्रेस में अब तक दल रहे रचनात्मक कार्यक्रम तथा आंदोलनों के अतिरिक्त वैकल्पिक रूप से राष्ट्रीय आंदोलन को समाजवादी विचारों के आधार पर पुष्ट करने का एक कदम भी था

जन्म



विस्मय

हागिया सोफिया का संग्रहालय से मस्जिद बनना: बदल रहा है समय

राम पुनियाजी

तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति इरादुगान, जो कई सालों से सत्ता में हैं, धीरे-धीरे इस्लामवाद की ओर झुकते रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदल दिया है। हागिया सोफिया मूलतः एक चर्च था, जिसे 15वीं सदी में मस्जिद बना दिया गया था। तुर्की ने अतातुर्क पुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में खलीफा जो कि ओटोमन (उस्मानी) साम्राज्य का अवशेष था, को अपदस्त कर धर्मनिरपेक्षता की राह अपनाई। खलीफा को पूरी दुनिया के

मुसलमानों के एक हिस्से की सहानुभूति और समर्थन हासिल था। अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता के प्रति पूर्ण और अद्विग प्रतिबद्धता थी उनके शासनकाल में हागिया सोफिया मस्जिद को संग्रहालय में बदल दिया गया। जहाँ सभी धर्मों के लोगों का दर्जा बराबर था और जहाँ सभी का स्वागत था।

पिछले तीन दशकों में वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन आए हैं। उसके पहले के दशकों में दुनिया के विभिन्न देशों में साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक शक्तों से मुक्ति के आंदोलन उभरे और लोगों का ध्यान दुनियावी मामलों

पर केंद्रित रहा जो देश औपनिवेशिक शक्तों के चंगुल से मुक्त हुए, उन्होंने औद्योगीकरण, शिक्षा और कृषि के विकास को प्राथमिकता दी। भारत, वियतनाम और क्यूबा उन देशों में से थे जिन्होंने अपने देश के वर्चित और संघर्षरत तबकों के संस्कारों पर ध्यान दिया और धार्मिक कटुतापक्षियों को किनारे कर दिया। इन देशों ने धर्म की दमघोड़ राजनीति से निजात पाने के लिए हरसंभव प्रयास किए। निरन्तर कुछ देश ऐसे भी थे, जहाँ के शासकों ने पुरोहित वर्ग से सहयोग कर सामंती मूल्यों को जीवित रखने का प्रयास किया और अपने देशों को



पिछड़पन से भक्ति दिलवान का कोई कोसिश नहीं की ऐसे देशों की नीतियाँ सांप्रदायिक और संकीर्ण सोच पर आधारित थीं। हमारे दो पड़ोसी- पाकिस्तान और म्यांमार इसी श्रेणी में आते हैं।

सन् 1980 के बाद से अनेक कारणों से धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्रिक रवितियाँ कमजोर पड़ने लगीं और धर्म का लबावा ओढ़े राजनीति का बोलबाला बढ़ने लगा इस राजनीति ने समावेशी मूल्यों और नीतियों को हाथिए पर टकेलना शुरू कर दिया राज्य को जन कल्याणकारी नीतियों से घटकाकर प्रारंभ कर दिया और शिक्षा और औद्योगिकरण के क्षेत्र में प्रगति को बाधित किया पिछले तीन दशकों में धर्म के नाम पर राजनीति का दबदबा बढ़ा है इस्लामवाद, ईसाईवाद, हिंदुत्व और बौद्ध कट्टरपंथियों की आवाजें बुलंद हुई हैं और ये सभी विभिन्न देशों को विकास की राह से भटका रहे हैं और समाज के बहुसंख्यक तबके को बदहाली में डकेल रहे हैं

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ईसाई धर्म के नाम पर प्रत्यक्ष और परोक्ष ढंग से अपीलें कर रहे हैं म्यांमार में अशिन विराधू बौद्ध धर्म के नाम पर हिंसा बढ़ा रहे हैं श्रीलंका में भी कमोवेश यही हालात हैं। वहाँ वीरप्पू जैसे लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है। भारत में हिंदुत्व की राजनीति पक्का चढ़ रही है। अफगानिस्तान के जलिलुल्लाह अपने देश में हो रही, बरम पश्चिमों और मध्य एशिया में भी गंडव कर रहे हैं। अफगानिस्तान में पगवान बुद्ध की मूर्तियों का विध्वनन इसका उदाहरण है। इसी तरह अरबों देशों में बाबरी मस्जिद का ध्वंस देश के इतिहास का एक दुःखद अध्याय रहा है जिसका इमनेमाल हिन्दू गुरुवादिनों ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए किया

ये तो इस बदलाव के केवल प्रत्यक्ष प्रभाव हैं। इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी अत्यंत विनाशकारी हुए हैं इससे नागरिकों और विशेषकर आमसंख्यकों के अधिकारों पर गहरी चोट पड़ चुकी है यह सब वैश्विक स्तर पर हो रहा है। कुछ दशक पहले तक साम्राज्यवादी ताकतें 'भूत दुनिया' खलाम एकधिकारवादी शासन व्यवस्था (सम्राज्यवाद) की बात करती थी 9/11

**भारत, वियतनाम और क्यूबा
उन देशों में से थे, जिन्होंने
अपने देश के वंचित और
संपर्षित तबकों के सरोकारों पर
ध्यान दिया और धार्मिक
कट्टरपंथियों को किनारे कर
दिया। इन देशों ने धर्म की
दमघाँट राजनीति से निजात पाने
के लिए हसंभव प्रयास किए।**

के बाद से, 'इस्लामिक आतंकवाद' उनके निशाने पर है इस समय पूरी दुनिया में अलग-अलग किस्म के कट्टरपंथियों का बोलबाला है। वे प्रजातंत्र और मानव अधिकारों को कमजोर कर रहे हैं

हमिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदल जाने की घटना को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए इरादुल्लाह ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत इस्लामबुल के मेयर के रूप में की थी उन्होंने इस पद पर बेहतर काम किया और आगे चल कर वे तुर्की के प्रधानमंत्री बने शुरुआती कुछ वर्षों में उन्होंने आर्थिक मोर्चे पर बहुत अच्छा काम किया बाद में वे आत्मप्रशंसा के जाल में फंस गए और सत्ता की भूख के चलते इस्लामिक पहचान की राजनीति की ओर झुकन लगे। उनकी नीतियों में देश के नागरिकों की जिंदगी महान तने लगे और नतीजे में म्यानीक संस्थाओं के चुनाव में उनकी हार हो गई

इसके बाद उन्होंने इस्लामवाद को पूरी तरह अपना लिया और इस्तांबुल की इस ध्वज हमारत- जो तुर्की की वास्तुकला का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है- को मस्जिद में बदलने का निर्णय लिया मुसलमानों का एक तबका इसे इस्लाम को जीत' बताकर जश्न मना रहा है। इसके विपरीत इस्लाम के वास्तविक मूल्यों और उसको मानवीय चेहरे को समझ रखने वाले मुसलमान इरादुल्लाह के इस निर्णय का कड़ा विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि इस्लाम में धार्मिक मामलों में

जोर जबरदस्ती के लिए कोई जगह नहीं है (तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन है और मेरे लिए मेरा दिन है) यह भारत में व्याप्त इस धारणा के विपरीत है कि देश में तानावर को नोक पर इस्ताम फैलाया गया।

इस्ताम के गंभीर अधेरा हमें यह याद दिलाते हैं कि एक समय पैगम्बर मोहम्मद और मुसलमानों को भी पश्चिनीयों में प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करते थे। कहने की जरूरत नहीं कि हर धर्म में अनेक पंथ होते हैं और इन पंथों के अपने-अपने दर्शन होते हैं। इस्लाम में भी शिया, सुन्नी, खोजा, बोह्र और सूफी आदि पंथ हैं और कई विधिविस्तार भी जिनमें इनफी और इनाकली शामिल हैं ईसाईयों में कैथोलिकों के कई उप-पंथ हैं और प्रोटेस्टेंटों के भी हर पंथ अपने आपको अपने धर्म का असली संस्करण बताता है सच तो यह है कि अगर विभिन्न धर्मों में कुछ भी असली है तो वह है अन्य मनुष्यों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव। धर्मों के कुछ पक्ष सत्ता की लोचुपता को ढकने के आवरण मात्र हैं इसी के चलते कुछ लोक जितने को उचित बताते हैं कुछ क्रुसेड को और अन्य धर्मबुद्ध को

हमिया सोफिया को मस्जिद में बदलने के निर्णय के दो पक्ष हैं चूंकि इरादुल्लाह की लोकप्रियता में तेजी से गिरावट आ रही थी इसलिए उन्होंने धर्म की वैमर्शियों का सहारा लिया। दूसरा पक्ष यह है कि दुनिया के अनेक देशों में कट्टरपंथियों का बोलबाला बढ़ रहा है सन् 1920 के दशक में कमाल अतातुर्क धर्म की अत्यंत शक्तिशाली संस्था से मुकाबला कर धर्मनिरपेक्ष नीतियाँ और कार्यक्रम लागू कर सके। पिछले कुछ दशकों में धार्मिक कट्टरता ने अपना सिर उठाया है। इसका प्रमुख कारण है अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं से मुकाबला करने के लिए अलकायदा को खड़ा करना और बाद में सोवियत युनियन का पतन, जिसके चलते अमेरिका दुनिया की एकमात्र विश्वशक्ति बन गया अमेरिका ने दुनिया के कई इलाकों में कट्टरतावाद को प्रोत्साहन दिया। इससे भीतर-भीर धर्मनिरपेक्षता की जमीन पर धर्म का कब्जा होता जा रहा है।

(हिंदी अनुवाद अमिताभ तरेनिका) =

पुस्तक समीक्षा

राजसत्ता, पूंजीसत्ता और धर्मसत्ता के गठबंधन खोलती पुस्तक

कज़मीर उप्पल

सुभाष गाताडे की पुस्तक 'चर्चाक के बारिस' अपने चार भागों के अन्तर्गत आनेवाले में एक साथ कई पुस्तक पढ़ने का आह्वान और चैलेंज भी है। सुभाष गाताडे अपनी 'प्रस्तावना' में कहते हैं कि 'हमारा बस्त एक ऐसा बस्त अब लिन्नार को ही दोह साबित किया जा रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बांदिशों की बात पुरानी पड़ गई है। फिलस्फत विचारों पर ही स्वाह छावाहें घंडराती दिख रही हैं। ठमी पर अधिकाधिक बांदिशें लगती दिख रही हैं। ऐसे बस्त में वह पुस्तक तर्क करने का साहस करने के लिए प्रेरित करती है। इस वस्त तर्क करना बहुत जरूरी है क्योंकि जनसमूह उद्वेलित और आंदोलित भी है। वस उसके गहन में मानव मुक्ति का फलसफा नहीं है। मानव मुक्ति का फलसफा क्या है? किसी देश के आम लोग तर्क मानव मुक्ति का फलसफा कैसे पहुंचता है? ये कौन लोग थे, जिनोंने मानव मुक्ति के लिए अपने प्राण तक उत्सर्ग कर दिए थे? वह कर सकते हैं कि हमारे देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के मानव मुक्ति फलसफा का वह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है।

चर्चाक के बारिस का पहला भाग बंद दिमागी एवं अतार्किकता के प्रश्नों पर केन्द्रित है। दुनिया के किसी भी अन्य इलाके को तुलना में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अतार्किकता तेजी से बढ़ी है और खतरनाक हो चली है। हमारे देश में भी पिछले चार वर्षों के विज्ञान कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में तथाकथित वैज्ञानिकों ने जो तर्क रखे हैं वे बहुत डरा देने वाले हैं।

किसी देश के तर्कवादी विज्ञान सरकार के दरबारी बनने लगे तो सरकार और देश के पतन का मार्ग खुल जाता है। हमारे देश के अग्रणी शिक्षा संस्थानों में विज्ञान की नई शाखा के तौर पर काउंटेरी या गैंगवैज्ञान का प्रवेश होने लगा है। कई शिक्षण संस्थानों में विश्वकशास्त्र को विज्ञान का दर्जा दिया जा रहा है। देश में राष्ट्र रक्षा महायज्ञ किए जा रहे हैं। आम की लकड़ी जलाने और गाय के दूध से बने घी को उस पर डालकर प्रदूषण कम किया जा रहा है।

आजकल देश की विधानसभाओं और बड़े संस्थानों में वास्तुदोष और भूत-प्रेत की छाया की चर्चा होती है। संविधान की धारा 51ए/एच स्पष्ट करती है कि सभी नागरिकों की बुनियादी जिम्मेदारी होगी कि 'यह वैज्ञानिक चिंतन मान्यता और अनुसंधान को विकसित करेंगे।' परंतु हमारे पूरे देश में जिम्मेदार पदों पर आसीन लोगों का अचरण भारतीय संविधान की मूलभावना के प्रांतिकृत बनता जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री तक विज्ञान सम्मेलनों तक में हान्यस्पद बयान देते हैं। इस संदर्भ में सुभाष गाताडे सोपनाथ मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाहर लाल नेहरू की स्मरण करते हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की सोपनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन के लिए तुलावा आया तब नेहरू ने यही कहा कि अंध व्यक्तिगत तौर पर उसमें शामिल हो सकते हैं। मगर एक सेकुलर मुक्त के राष्ट्रपति के तौर पर नहीं अंततः राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के तौर पर नहीं बल्कि आम नागरिक के तौर पर उद्घाटन में शामिल हुए थे। इस पुस्तक में हमारे देश में बढ़ते जा रहे अतार्किक और

अवैज्ञानिक सोच के इतने उदाहरण हैं कि रीने और हंसने को मन करना है।

पुस्तक के पहले भाग का दूसरा आलेख 'चंद्रबुद्धिपन' पर है। इसमें साधुओं, ब्राह्मणों और महात्माओं के साथ-साथ पढ़े-लिखे लोगों और नेताओं के अनगिनत किस्से हैं। इसी अध्याय में 'डेमोक्रेट्स से चर्चाक' में ग्रीक एवं भारतीय प्राचीन दर्शन पर प्रकाश डाला गया है। वह अच्छा होता यदि ग्रीक और भारतीय दर्शन पर एक स्वतंत्र और अधिक विस्तृत एक स्वतंत्र भाग हो होता। 'हर्म' से चंद्रबुद्धि कौन नहीं आलेख का एक हिस्सा बनने से मानों पुस्तक का मुख्य स्वर ही दब गया है। डेमोक्रेट्स से चर्चाक तक का इतिहास मतलबता है कि तर्कशीलता और वैज्ञानिक सोच का दबने की प्रचुर परत प्राचीन रही है। आज जो कुछ दिख रहा है वह एक ऐतिहासिक जिडम्बा का ही दूसरा चरण है। वह सब हमारे समय में हो रहा है इसलिए दर्शक बने रहने का अर्थ अपनाधी बने रहना है।

डेमोक्रेट्स ग्रीस में ईसा पूर्व 460 वर्ष पूर्व पैदा हुए थे। उन्हें अणु सिद्धांत का जनक/प्रस्तावक भी कहा जाता है। डेमोक्रेट्स इंस्वर पर लोगों के विश्वास को भी समाप्त करना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि इन विश्वासों को इसलिए लाया गया ताकि ऐसी परिघटनाओं का स्पष्टीकरण किया जा सके जिनके लिए तब तक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं थे। प्राचीन ग्रीस में डेमोक्रेट्स की उपेक्षा हुई सुकरात के शिष्य प्लेटो सुकरात चाहते थे कि डेमोक्रेट्स की सारी किताबें जला दी जाएं। दर्शनिक बर्टांड रसल के अनुसार प्लेटो का यह इच्छा



चार्वाक के वारिस

सुभाष गाताडे



शायद इस तरह पूरी हुई कि आज डेमोक्रेटस की रचनाएं बिल्कुल अपलब्ध नहीं हैं। हम फ्लेटा का दूसरा चेहरा देखते हैं, जिसकी चर्चा कभी नहीं हुई है।

इस आलेख से स्पष्ट होता है कि अनेक दार्शनिकों के वैज्ञानिक आंदोलन की धारा के विरुद्ध टकराव की स्थिति सदैव बनी रही है। ग्रीक दार्शनिकों की तरह भारत में भी चार्वाकों और ब्राह्मणवादी दर्शनों के

पुस्तक : चार्वाक के वारिस
लेखक सुभाष गाताडे
प्रकाशक . ऑथर्स प्राइड
पब्लिशर प्र. लि , दिल्ली
पृष्ठ 314 मूल्य 399/-

पुस्तक समीक्षा

बीच संघर्ष चलता रहा है। आज हमारे देश में जो कुछ अनाकिक हलचल हो रही है वह उसी पुरानी ब्राह्मणवादी टकराव का एक आधुनिक रूप है। आश्चर्य की बात है कि यह सब हमारे देश में इक्कीसवीं शताब्दी में हो रहा है।

इंस्वर की अवधारणा को प्रशस्तिकर करने वाले धर्म के बोझ से मानवीय जीवन की मुक्ति की बात करने वाले ग्रीक दार्शनिकों की तुलना भारत के चार्वाक से भी की जाती है। ग्रीक दार्शनिकों की तरह चार्वाक के विचार भी धृष्टा के शिकार हो रहे हैं। अगर डेमोक्रेटस की रचनाएं गायब न हो गईं उसी तरह भारत में चार्वाक की रचनाएं एवं उसकी धारा के ग्रंथ भी नष्ट कर दिए गए। चार्वाक का एक श्लोक ही चर्चा में रखा गया है जिसमें वे जब तक जीना चाहिए सुख से जीवन चाहिए कहते हैं। चार्वाक के अन्य श्लोकों की चर्चा नहीं की जाती है। चार्वाक के सिद्धांतों का निष्पेक्ष संक्षेप में इस प्रकार है। पवित्र साहित्य को असत्य मानना चाहिए, कोई भगवान नहीं होगा, कोई आत्मा नहीं होगी, सभी भौतिक तत्वों से संघटित है आदि। चार्वाक यह भी कहते हैं कि पूर्ण धर्मशास्त्रियों द्वारा दिखाई गई झूठी आशाओं का शिवर होने वाले पुरुष प्राणी हैं।

भारतीय दर्शन में आध्यात्मिकता का प्रधान स्वर में लेखक प्रश्न उठाता है कि भारतीय संस्कृति की एक खास किस्म की छवि ही क्यों प्रचलित हुई? इसका एक सिरा उप-निवेशवादी विचारकों की रणनीति से और दूसरा सिरा धृष्टा एवं नफरत पर टिके अपने एजेंडे को आगे लेकर बढ़ रही ताकतों ने अपने पौरौसी प्रकसर को पूरा करने के लिए अतीत की खास तरीके की व्याख्या शुरू की है। ब्राह्मणवादी संस्कृति के विस्तार ने भारत में वैज्ञानिक कामकाज एवं आयुर्वेद चिकित्सा के अनुसंधान को बाधित किया। भारत में आयुर्वेद के उदय का कालखंड इसापूर्व सातवीं-छठवीं सदी है जिसका स्थितिभक्तकाल बौद्ध और साम्राज्य में दिखाई देता है। बौद्ध धर्म की अवधि के बाद वैदिक हिन्दू धर्म के उभार के साथ उसकी लोकप्रियता में कमी आ जाती है। इसका

पुस्तक समीक्षा

एक प्रमुख कारण हुआ। दूसरे इसके कारण वैज्ञानिक सोच आगे नहीं बढ़ी।

भारत में मायवाद के बहुते प्रभाव ने न केवल चिकित्सा विज्ञान को पीछे धकेला उसी तर्ज पर खगोल विज्ञान की प्रगति को नुकसान पहुँचाया। भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बातें करने वालों पर ब्राह्मणों के पायाजल का शिकंजा कस रहा था। उसी समय इतावली दार्शनिक बुने को 16 फरवरी 1600 को नरन के आदेश पर रोम के चौहाने पर जिन्दा जला दिया गया था। ऐसी सहादतों ने ही यूरोप में प्राकृतिक-विज्ञान और आधुनिक दर्शन की आगें बहाया था। आपो दीपो भव अलेख में म्नामी दानन्द, विवेकानन्द एवं महात्मा ज्योतिबा फुले के महाने कुछ बातें रखी गई हैं। इन्होंने वर्ष के मायाजाल का शिकंजा तोड़ने के अभियान चलाकर एक नई प्रगतिवादी लहर पैदा की थी।

पुस्तक के दूसरे भाग में दो आलेख हैं नौनवालों से दो बातें और 'खुदा हमें इन विश्वगुरुओं से बचओ' इसमें लेखक ने नौनवालों की शिक्षा और जाति से संबंधित कई प्रश्न उठाए हैं। इसकीसवीं सदी में भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने की बात अस्सा चलती है। सवाल उठता है कि समाज जो इस कदर समुदाय, जाति आदि के बंधनों में उलझा हुआ हो, जहाँ पर एक दूसरे को नीचा समझने वाली चार हजार से अधिक जातियाँ-उपजातियाँ हों, जहाँ प्रेम जैसे बेहद निजी एवं आत्मीय रिश्ते पर सपाज एवं परिवार की पहरेदारी परम्पराओं के नाम पर आज भी मौजूद हो, वह देश कैसे आर्थिक महाशक्ति बनेगा।

सुभाष गालाडे मेगास्थनिस, अल बरुनी एडमंड बुके आदि के माध्यम से भारतीय समाज का मूल्यांकन प्रस्तुत करते हैं। इसे पढ़कर समझ आता है कि उस समय भी जाति व्यवस्था में समाज बाँधा हुआ है। हम अपनी संस्कृति की महानता की बातें करते हुए आत्मगुट रहते हैं परंतु आज भी विश्व के विद्वानों को हमारी सामाजिक व्यवस्था अहर्चर्यजनक लगती है। मुहम्मद चक्रवर्ती ने अपनी किताब 'राज सिन्धु' में लिखा है कि 'उपनिवेशवाद की विरासत ने दीपम दर्न के भारतीयों की

एक ऐसी राष्ट्रीय पहचान को मजबूती प्रदान की जो आज भी स्वतंत्रता की अखंड रंग से ऊँचा खाने के लिए अभिव्यक्त होती है।' इस संदर्भ में डॉ. अम्बेडकर के विचारों का काफी विस्तार से पुस्तक में स्थान मिला है।

पुस्तक का तीसरा भाग हेडगेवार-गोलतलकर बनाम अम्बेडकर नेहरू अम्बेडकर बहुसंख्यकवाद की चुनौती तथा पहचान की राजनीति और काम का भविष्य के तीन आलेखों में प्रस्तुत है। नेहरू अम्बेडकर और बहुसंख्यकवाद की चुनौती में उठाए गए प्रश्न देश के समकालीन प्रश्न हैं। आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या

उस समय नेहरू कितने सही थे क्योंकि आज हम बहुसंख्यकवाद समुदाय की साम्प्रदायिकता को उसके राष्ट्रवाद के तौर पर देखने की अभिशप्त हैं। अम्बेडकर इस संबंध में कहते हैं कि अगर हिन्दू राज हकीकत बनता है तो यह इस देश के लिए सबसे बड़ी तबाही का दिन होगा।

और चुनौती बहुसंख्यकवाद ही है। हमारे देश में बहुमत की सरकार की नहीं बहुसंख्यकों की सरकार की बात होनी लगी है। इसी से हिन्दू और मुस्लिम में बढ़ती साम्प्रदायिकता और कटुता को समझा जा सकता है। बहुमत को नकारने का अर्थ भारतीय संविधान को नकारना है। हम यह नारा सुनते हैं कि 'जो हिन्दू हिंदू की बात करेगा वही देश पर राज करेगा।' यही बहुसंख्यकवादियों की राजनैतिक चलाकी ही है कि उन्होंने बहुमत के राज के स्थान पर 'बहुसंख्यकवाद' के हितों का नारा

लगाना शुरू कर दिया। इस देश में बहुसंख्यकों के राज का सपना दिखाकर अल्पसंख्यकों के विरुद्ध नज़र फैलवाया जा रहा है। जवाहर लाल नेहरू ने 1950 के दशक में बहुसंख्यकवाद के खतरों को पहचान लिया था। नेहरू के अनुसार 'जब अल्पसंख्यक समुदाय साम्प्रदायिक होता है, तो आप इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मगर बहुसंख्यकवाद समुदाय की साम्प्रदायिकता को राष्ट्रवाद के तौर पर समझे जाने की स्थिति अमूर्त पर रहती है।

उस समय नेहरू कितने सही थे क्योंकि आज हम बहुसंख्यकवाद समुदाय की साम्प्रदायिकता को उसके राष्ट्रवाद के तौर पर देखने की अभिशप्त हैं। अम्बेडकर इस संबंध में कहते हैं कि 'अगर हिन्दू राज हकीकत बनता है तो वह इस देश के लिए सबसे बड़ी तबाही का दिन होगा।' हमारा देश एक उदारवादी जनतंत्र से एक किस्म के बहुसंख्यकवादी जनतंत्र में रूपांतरित होता जा रहा है। भारतीय राजनीति के केंद्र में हिन्दुत्व वर्चस्ववादी ताकतों के साथ इस प्रक्रिया में तेजी आई है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने जनता को इस बात के लिए आशंकित किया था कि अगर वह सचेत नहीं रही तो भारत 'हिन्दू पाकिस्तान' बन सकता है। इस पुस्तक के लेखक ने संविधान सभा को लेकर डॉ. अम्बेडकर के सुझावों एवं कार्यों का विस्तृत लेखा-जोखा दिया है। इसी तरह 'हिन्दू कोड बिल' अम्बेडकर द्वारा नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा देने का प्रमुख कारण बना था। इस बिल के विरोध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रदर्शन किए थे।

डॉ. अम्बेडकर ने 1949 को संविधान सभा में अपने भाषण के दौरान तीन चेतावनियाँ दी थीं- 1 संविधान पद्धतियों का पालन 2 अपनी आज्ञादियाँ को किसी महान शक्ति के चरणों में गिरनी न रखना 3 राजनीतिक जनतंत्र को सामाजिक जनतंत्र बनाना। आज हम देख रहे हैं कि देश अम्बेडकर की इन चेतावनियों से जुड़ा रहा है। देश के समस्त सबसे बड़ी चेतावनियाँ किसी महान 'राज' के चरणों में अपनी आज्ञादियों को गिरवी

रखने का खतरा है। इसीलिए देश के पूँजीवादी परानों के झंडिया सन्तुह 'महान-शास्त्र' को रचने के षड्यंत्र में शामिल है।

डॉ अम्बेडकर ने चेतावनी दी थी कि हमें नायक पूजा बचना होना उनके अनुसार 'यह चेतावनी किसी अन्य देश की तुलना में भारत के संदर्भ में जल्दी है क्योंकि वहाँ भारत में, भक्ति या जिसे आप शक्ति का सरता या नायक पूजा का मार्ग कह सकते हैं वह राजनीति में इस कदर भूमिका निभाती है, जैसा दुनिया के किसी अन्य देश में दिखाई नहीं देता। धर्म में शक्ति भले ही आत्मा के मोक्ष/मुक्ति का रास्ता खोल दे मगर राजनीति में भक्ति या नायक पूजा अवनीत/पतन अधोगति का और अंततः तानाशाही का पक्का मार्ग है।' हेडगेकार-गोलवलकर खाना अम्बेडकर आलेख भाजपा के प्रवक्ता डॉ विजय सोनकर शास्त्री द्वारा लिखित तीन किताबों पर चर्चा की गई है। इसमें डॉ अम्बेडकर समता की बात और हेडगेकार समासता की बात करते हैं। इसके लिए दोनों ने भिन्न मार्ग अपनाए हैं।

इस आलेख में कई प्रश्न उठाए गए हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघन तो समय-समय पर प्रस्तुत किया जाता है। अस्पृश्यता का जन्म इस्लाम आगमन के बाद, हिन्दू चर्मकार जाति-एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशीय इतिहास, संत रविदास का हिन्दुत्वकरण, जातिप्रथा के उद्गम पर चर्चा और मनु के कानून के उपसोपबन्धों में विभाजित है। डॉ अम्बेडकर के विचारों को बहुत कौन और कैसे आलेख में विस्तारपूर्वक चर्चा है। पुस्तक के तीसरे भाग का अंतिम आलेख 'पहचान की राजनीति और शास का भविष्य' है। इसमें पूरी दुनिया में हुए राजनैतिक और सामाजिक बदलावों में वाम की भूमिका और भविष्य पर एक संक्षिप्त नोट है। यह स्पष्ट रूप से कुछ भी सिद्ध नहीं करता है। लेखक सुभाष गाताडे कई कार्यक्रमों का लेखा-गोखा देते हुए पूँजीवाद और साम्यवाद की उभरती कई प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है पर वे पक्ष के भविष्य की लेकर कोई नई तस्वीर नहीं बनाते हैं। लगता है लेखक अपने पास उपलब्ध सम्प्राप्ति को आलेख पर

धसा करता जा रहा है।

पुस्तक का अंतिम और चौथे भाग में राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तकत्रयी अंधविश्वास उत्खनन-विचार (पहला भाग) और अंधविश्वास उत्खनन सिद्धांत (तीसरा भाग), जिनके रचयिता डॉ दाभोलकर हैं की समीक्षा प्रस्तुत है। इन पुस्तकों में यह विचार स्पष्ट उभरता है कि धर्म हमको आज्ञा देता है कि 'विश्व का राज मैं जान चुका हूँ अब केवल मेरी आज्ञा का पालन करो' इसके वाक्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण वस्तु अथवा घटनाओं को जानने की तथा अज्ञात तत्व को पढ़नाल जारी रखने की बात करता है।

ब्राह्मणवादी संस्कृति के विस्तार ने भारत में वैज्ञानिक कामकाज एवं आयुर्वेद चिकित्सा के अनुसंधान को बाधित किया। भारत में आयुर्वेद के उदय का कालखण्ड ईसापूर्व सातवीं-छठवीं सदी है जिसका स्वर्णिमकाल बौद्ध मौर्य साम्राज्य में दिखाई देता है।

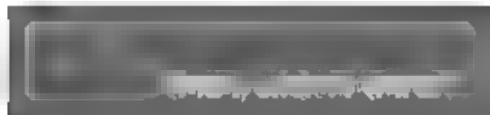
डॉ दाभोलकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सरल परिभाषा देते हैं- किसी घटना की पृष्ठभूमि में उपस्थित कार्य कारण को जान लेना अथवा दो भिन्न घटनाओं के बीच के पुरक संबंधों को जान लेना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि 'किसी भी ग्रंथ में लिखे हुए अथवा किसी अधिकारी व्यक्ति के कहे हुए वचन को सच मानना गलत है क्योंकि अंतिम सत्य का निष्कर्ष प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा निरीक्षण होता है। मैं आगे कहते हैं कि यूरोप में वैज्ञानिक अपनी बात को समाज के बले बांधने के लिए अपने

सर्वस्व की बाजी लगा देते थे भारत में अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण तो सुविधा से स्वीकार किया गया परंतु इसके लिए आवश्यक निडर मारसिकता नहीं पनप पाई।

प्रसिद्ध मराठी लेखक बाबुराव बागुल का वक्तव्य हमारे पुरे समाज की समीक्षा का आधारभूत पाठ बन पड़ा है। यह वक्तव्य इस पूरी पुस्तक का सारतत्व है 'देवताओं धर्मियों और चर्चियों का यह देश इसलिए क्या यहाँ सब कुछ अमर है, वर्ण अमर जाति अमर, अस्पृश्यता अमर।' युग के बाद युग आए बड़े बड़े चक्रवर्ती आए दार्शनिक आए। फिर भी अस्पृश्यता विषमता अमर है यह कैसे हो गया? किसी भी महाकवि पंडित, दार्शनिक सन्नाधारी संत की आंखों में यह अमानुषिक व्यवस्था चुभी क्यों नहीं? बुद्धिजीवियों संतों और सामर्थ्यवानों का वह अधापन, यह संवेदनशून्यता दुनियाभर में खोजने पर भी नहीं मिलेगी! इससे एक ही अर्थ निकलता है कि यह व्यवस्था बुद्धिजीवियों संतों और राज करने वालों की मंजूर दी वाली इस व्यवस्था को बनाने और उसे बनाए रखने में बुद्धिजीवियों और शासकों का हाथ है।

अन्वेषणीय है कि प्रत्येक आलेख के अंत में दी गई संदर्भ सूची पुस्तक को ऐतिहासिक दस्तावेज बनाती है। इस पुस्तक के संदर्भों के आधार पर इस विचारधारा को आगे बढ़ाया जा सकता है। डॉ दाभोलकर कहते हैं कि जिस देश में चावाक, लोकावत, बुद्ध की परंपरा थी वहाँ 11-12वीं सदी से आगे अठारह सौ साल तक लोग प्रश्न पूछना क्यों भूल गए।

लेखक ने परिशिष्ट के रूप में भी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का अत्यंत संक्षेप में परिचय भी दिया है। यह परिशिष्ट अत्यंत महत्वपूर्ण बन पड़ा है हमारे देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विवेक को आंदोलित करने वाली पुस्तकों बहुत कम चर्चा में रही है। इसलिए चावाक के वारिष्ठों के लिए तर्कसंगत सोच को विकसित करने वाली पुस्तकों से परिचय कराना भी एक सक्रिय किस्म का मूल्य-परिवर्तन का कर्मशील संवाद है। ■



यूपी में शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्युस का पोस्टर अभियान

विद्यार्थी युवजन सभा और न्याय मोर्चा ने उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करने व सीबीआई जांच करने की मांग की और लोकडाउन के दौरान पोस्टर प्रदर्शन किया।

विद्युस और न्याय मोर्चा मऊ जिले के दरियाबाद, इटौल कीर्वापुर सहोपर, अक्बलही मुबारकपुर चौधौसी, मंडौ, सिपाह और आजमगढ़ जिले के अजमलगढ़, जौनपुर, लाटघाट, बलपुर में व्यापक स्तर पर पोस्टर अभियान चलाया। विद्युस ने 14 जुलाई की विज्ञापित में कहा है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म कर परीक्षा रद्द करने व सीबीआई जांच करने तक पोस्टर अभियान जारी रहेगा।

विद्युस के संयोजक शैलेश कुमार ने विज्ञापित में बताया है कि न्याय मोर्चा एवं विद्युस से जुड़े छात्र इस पोस्टर को प्रदेश के सभी जिलों में लगाने की योजना के साथ काम कर रहे हैं। विद्यार्थी युवजन सभा के जिला संयोजक मुंशी कुमार ने कहा कि सरकार अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोपियों को निर्दोष नहीं कर पाई है। इसका मतलब साफ है कि सरकार भर्ती में भ्रष्टाचार के मामले को दबाना चाहती है, जो गरीब किसान मजदूर परिवार से आने वाले छात्रों के साथ अन्याय है। मंडल प्रभासी राणा प्रताप चौहान ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई जांच व परीक्षा रद्द की मांग करते हुए पोस्टर जारी किया और जगह जगह पर पोस्टर लगाकर आंदोलन को व्यापक करने की बात कही। विद्युस की सदस्य अचना मोर्च ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है जो जगजाहिर है फिर भी उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार उसे दबाना और तानाशाही तरीके से भर्ती को पूरा करना चाहती है। निमका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विद्यार्थी युवजन सभा के संयोजक एवं न्याय मोर्चा संयोजन समिति के सदस्य शैलेश कुमार ने कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा कर पचा परीक्षा से 1 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। रोज कोई ना कोई पकड़ा जा रहा था लेकिन जैसे ही सरकार को लगा कि अब उसके बड़े बड़े मंत्री और विधायक एवं अधिकारी का नाम खुलेंगे वह पकड़े जाएंगे तो उसने जांच को दबाने की कोशिश की और उसमें एंबीपोली कर रही है।

पोस्टर जारी करते व लगाने में विद्यार्थी युवजन सभा के भुनरावा मोर्च खोहन चौहान, सधिन खान्नी अमरेज, आदित्य अकिवा सुमन, चंद्रेश मोर्च, रंजित कुमार, मधु और न्याय मोर्चा के साथी भी शामिल रहे।

पर्यावरण रक्षकों को नमन

2019 में पूरी दुनिया में जल, जंगल, जमीन, को बचाने में 212 लोगों की जानें गईं। यह जल स्थंडिल क्तिनेस नामक संस्था द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताई गई है। सबसे ज्यादा खेतिहारी से

अधिक हत्याएं दक्षिण अमेरिका में हुईं। कोलंबिया में 64, फिलीपींस में 43, ब्राजील में 24, मैक्सिको में 18, हाइडुस में 14, ग्वाटेमाला में 12, भारत में भी 6 लोग शहीद हुए। अफ्रीका महादीप में 7 मामले सामने आए। लेकिन जानकारों का कहना है कि अफ्रीका में सभी मामले दर्ज नहीं किए जाते। यूरोप (रोमानिया) में केवल 2 लोगों की जान गई। साथ ही यह बात भी महत्वपूर्ण है कि हर 10 हत्याओं में 1 महिला है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यदि घर का कोई सदस्य पर्यावरण संरक्षण का काम कर रहा है तो भी घर की महिलाओं पर हमले वीन हिंसा की आशंका बनी रहती है। क्षेत्र के हिसाब से देखें तो खनन में 50, जंगल की बचाने में 24, कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों में 34 (इसमें 85% हत्याएं एशिया के देशों में हुईं)। हत्याएं हुई हैं इन हमलों में से करीब 40% हमले आदिवासियों/मूलवासियों पर ही हुए, जो कि खेती तौर पर जल, जंगल, जमीन से जुड़े होते हैं और अब इनकी आबादी पूरी दुनिया की जनसंख्या की केवल 5% ही है। जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण बचाने के लिए संघर्ष कर रहे इन जैसे सभी पर्यावरण रक्षकों को संरक्षण देने और बचाने की जिम्मेदारी अब समाज के उन सदस्यों को करनी होगी, जो नंद, शालाब, जंगल, जमीन बचाने में विश्वास करते हैं और मानते हैं कि पूँजीवाद, साम्राज्यवाद ने विश्व मनुष्य का ही शोषण ही नहीं किया, प्रकृति का भी शोषण किया है। कंपनियों, सरकारों और गामी गिरामी राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर भरोसा करना, धोखा खाना होगा।

जलधारा अभियान, जयपुर

जम्मू-कश्मीर में नदी संपदा की लूट

(जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए हटाकर उसका स्टेट्स बदले एक खाल से अधिक हो गया। अब शेष भारत के जंगल/कफनवां वहां जमीन, जलवायु खरीद सकती है। वहां व्यापारिक आर्थिक खनन कार्य भी कर सकती है। इस बदलाव के बाद वहां की नदियों का किस तरह शोषण हो रहा और उसमें सरकार-प्रशासन किस तरह से मददगार साबित हो रहे हैं। इस आलेख से उसका सिर्फ कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें दिए गए तथ्यों और जानकारियों के लिए जलधारा अभियान द बंडपोल नेट और श्री अतहर परवेज का अग्रभार व्यक्त करता है।)

पिछले कुछ समय से खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर की नदियां में से रेत, बजरी, खोल्ट्स का गैर कानूनी खनन खुल हो रहा है। जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा नदियों के पेटे से रेत, बजरी निकालने के लिए ऑनलाइन नीलाभी के कुछ दिन बाद ही ठेके प्राप्त करने वाली सफल कंपनियां ने बिना किसी पर्यावरण अनुमति के ही रेत, बजरी का खनन शुरू कर दिया। खानकार ज़ेल्म और उसकी सहायक नदियों में जबकि वहां के नागरिकों और विशेषज्ञों के अनुसार इसे गैर-कानूनी करार दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा न करके सरकार ने 30 जुलाई 2020 को पर्यावरण मंजूरी देने में तेजी लाने के अदेश निकाले हैं। नया आदेश जारी करने का

कारण विकास कार्यों के लिए जरूरी साधनों की कमी आ जाना, जो कि कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए अति आवश्यक है बताया गया। तर्क दिया गया कि इस आदेश में सरकार ने ध्यान देते हुए जान लिया उसका खतरा है कि पहले वाले अलॉट की जिन शर्तों पर अनुमति दी गई थी, वही अनुमति उन्ही शर्तों के साथ नए अलॉटों को ट्रांसफर मान लेनी चाहिए और यह नया अलॉट इस अनुमति के साथ, नई अनुमति मिलने तक या फिर 2 साल तक खनन कार्य कर सकता है। इस तरह से सरकार अपने ही पहले दिए आदेशों के साथ-साथ अपने ही संस्करणों के विशेषज्ञों द्वारा दी गई सलाह के विरोध में आ गई। ध्यान देने की बात है कि जून 2020 में ही सरकारी संस्था जम्मू कश्मीर एक्सपर्ट एग्जक्यूटिव कमिटी ने रेत खनन के रीग कानूनों खनन होने की चेतावनी दी थी। नियमों के मुताबिक यदि खनन का एरिया 5 हेक्टेयर से ज्यादा है तो पर्यावरणीय अनुमति के लिए जन सुनवाई भी जरूरी है। जबकि 70% से ज्यादा सफल नीलामी ठेके 5 एकड़ से ऊपर के हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि शायद ही कोई जन सुनवाई हुई हो।

जम्मू-कश्मीर एनवायरनमेंट अप्रोप्रियेट कमिटी ने दिसम्बर 2019 में सरकार को यह सलाह दी थी कि ड्रेलम और उसकी सहायक नदियों में तब तक कोई खनन कार्य नहीं करवाना चाहिए जब तक कि वैज्ञानिक आधार पर बसिन चार्टर यह पता नही लग जाए कि कौन कौन से एरिया खनन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं और वह सभ जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। लेकिन इस सलाह के बावजूद ड्रेलम और उसकी सहायक नदियों में रेत/बजरी निकालने के लिए पुलवामा, श्रीनगर, बावमूला जिले की नदियों में 72 करोड़ (720 मिलियन) रुपये के ठेके 5 साल के लिए दिए गए। जम्मू कश्मीर के इन्विजन और फ्लूइड करंट्स विभाग के इंजीनियर्स का कहना है कि जन नदियों के घेरे में से रेत, बजरी का बड़ी मात्रा में खनन होगा तो नदी के बहाव की बलॉसिटी (वेग) बढ़ जाएगी। यह बड़ी मात्रा में खोद लक्ष्मी और इससे अकसमात् की नदियां, तलाबों में गाव का जमाव भी बढ़ेगा। इस तरह बाढ़ नियंत्रण प्रणाली वहां के पर्यावरण, पारिस्थितिकी और निवासियों को प्रभावित करेगा। इस बार की नीलामी 21 दिसंबर 2019 को ऑनलाइन शुरू की गई। जबकि गज्ज में अगस्त 2019 के पहले सप्ताह से जनवरी 2020 के तीसरे सप्ताह तक इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह बंद थी। बाद में कम स्तर पर जाली 2जी सेवा शुरू की गई। यहां यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि नीलामी में इस बार राज्य से बाहर की कंपनियों ने भी भाग लिया और इस बार नीलामी में सफल अधिकांश कंपनियां राज्य से बाहर की ही हैं। श्रीनगर में ड्रेलम नदी के सभी 10 ब्लॉक्स बाहर की कंपनियों को पांच करोड़ रुपये में मिले। पुलवामा में कुल 36 ब्लॉक्स में से 14 (40%) राज्य की कंपनियों ने लिए और 22 ब्लॉक्स बाहर की कंपनियों ने लिए। पूरे जम्मू-कश्मीर में राज्य से बाहर की कंपनियों ने 48 करोड़ के ब्लॉक्स लिए। 10 फरवरी 2020 को हुई नीलामी में 28 में से 19 ब्लॉक बाहर की कंपनियों ने 19 करोड़ रुपये में 5 साल के लिए ले लिए।

स्थानीय ठेकेदारों का कहना है- वह बहुत ही अन्यायपूर्ण बात है कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों को नेटवर्क के दिनों में इस तरह ऑनलाइन बिकवाली के लिए जाल दिया गया। हम किसी भी हाल में बाहर की कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और वे हमारे संसाधनों को बाहर ले जाएंगे। इस तरह यह स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार का भयंकर संकट पैदा कर सकता है। इससे घाटी में गरीबी बहराएगी पर्यावरण संकट बढ़ेगा और सामाजिक-राजनैतिक विघटन में तेजी आ सकती है। क्योंकि दूरदराज की कंपनियों में स्थानीय जरूरतों को पूरा करने की इच्छा ही नहीं होती।

जसवंत अग्निषन, जम्मू

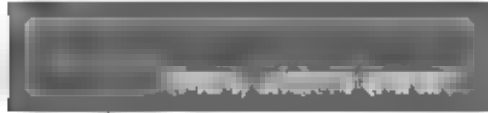
नई शिक्षा नीति-2020 को शिक्षकों ने खारिज किया

नई दिल्ली- अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार घंघ की ओर से 4 सितंबर को नई शिक्षा नीति-2020 पर विचार करने के लिए शिक्षकों की ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। इसमें शिक्षकों ने नई शिक्षा नीति को गरीब-पिछड़ा विरोधी बताया हुए इसे खारिज करने की मांग की। इस बैठक में सर्वसम्मति से राय बनी कि-

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित की गई नई शिक्षा नीति-2020 के खानू होने पर 85 से 90 फीसदी बच्चे बेहतर नैतिक पूर्णकालिक तालीम से बाहर हो जाएंगे और या तो निचले दर्जे की तालीम पाएंगे या बचपन से ही कम पैसे वाली मजदूरी करने या पारिवारिक बंधों में लग जाएंगे। इससे असल में राष्ट्र को तत्काली को नुकसान होगा।

हमारी अबादी में अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग, धार्मिक एवं भाषिक अल्पसंख्यक, शहरी व ग्रामीण गरीब, सामाजिक रूप से वंचित समूह और स्त्रियों शामिल है। शिक्षा नीति 2020 में वंचित अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े तत्काल के लिए आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है। यह न केवल सामाजिक न्याय की व्यवस्था को कमजोर कर देगी बल्कि लोक शिक्षा व्यवस्था को ही तहस नहस कर देगी और शिक्षा के खुले आम व्यापार को खासा बढ़ावा देगी। व्यावसायिक शिक्षा के नाम पर यह शिक्षा को केवल कारीगरी पढ़ाने तक सीमित करेगी और हर विषय में दो तरह के पाठ्यक्रम को लागू करेगी। इससे बच्चों से मौजूदा तक खीन लिया जाएगा कि वह कम से कम पांच सालों तक विज्ञान गणित समाज विज्ञान और भाषाओं की तालीम ले सकें।

शिक्षा नीति 2020 शिक्षकों तथा शैक्षणिक संस्थाओं को अकादमिक स्वायत्ता छीन लेगी। यह नीति राज्य सरकारों के जरूरी अकादमिक और शैक्षणिक फैसले लेने के अधिकार को खत्म करके संविधान के संघर्षक दायें को ही खत्म कर देगी। जब शिक्षा-व्यवस्था पर इस तरह का गलत एजेंडा थोपा जा रहा हो तो भारत के नागरिक, शिक्षक और बुद्धिजीवी वर्ग होने के नाते इस पर अपनी राय प्रकट करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं।



शिक्षा नीति 2020 का दावा है कि बुनियादी सुधारों के केंद्र में अध्यापकों को रखा गया है। उनकी आजीविका, आत्मसम्मान गरिमा और स्वायत्तता को सुनिश्चित किया गया है, ताकि बेहतर तालीम मुमकिन हो। पर ऐसा हो पाने के लिए जो ज्वलंत मुद्दे हैं जैसे ठेके और तदर्थ शिक्षकों, 200 पॉइंट रेस्ट, पेंशन आंगनवाड़ी, इसीसीई कार्यकर्ताओं की नियमितोकरण और महिला शिक्षकों के मातृत्व अवकाश आदि पर यह नीति खामोश है। अगर शिक्षा नीति 2020 लागू होगी है तो आंगनवाड़ी/ इसीसीई कार्यकर्ताओं की स्थिति और कमजोर हो जाएगी।

शिक्षा नीति 2020 निवोक्ताओं को प्रोवेशन पेरिवड जड़ाने की छूट देती है और इससे अध्यापकों का शोषण बढ़ेगा। इसमें यह प्रावधान है कि प्रारंभिक स्तर से लेकर स्कुली तालीम के विविध स्तरों पर बड़े पैमाने पर 'स्वैच्छिक कार्यकर्ता' 'सापानिक कार्यकर्ता', सलाहकार, स्थानीय सम्पानित शक्तिवत, स्कुलों के पुराने छात्र सक्रिय और स्वस्थ बरिह-नगरिक और सपाज में सार्वजनिक मुद्दों में रुचि रखने वाले लोगों को अनौपचारिक अपरिभाषित भूमिका में शामिल किया जाएगा ताकि इस तरह तालीम में वैचारिक एजेंडा बदलने के लिए पिछले दरवाजे से अपने कैडर की भर्तों को जा सकें।

अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच ने सीबीएसई पाठ्यक्रम से पाठों को हटाने की निंदा की

नई दिल्ली। भारत सरकार ने शिक्षा प्रणाली पर दोतरफा खतरनाक हमला बोल दिया है। एक ओर, 24 जून 2020 को उसने प्रारंभिक बालपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) से बहरवीं कहा तक की स्कुली शिक्षा की पूरी प्रणाली की संगठन प्रशिक्षण और प्रशासन को खोखला वैचारिक कर विरोधाधिकार धिक्क बैक को लीप दिया है। इससे संविधान द्वारा प्रदत्त शिक्षा की स्वतंत्र, आवश्यक सार्वजनिक प्रणाली के रूप में इसे कजभूत और विकसित करने के बजाय शिक्षा का एक निजीकरण, वाणिज्यिक और निगमिकृत प्रणाली में रूपांतरित करने का पथ प्रगस्त हो गया है।

अब, 7 जुलाई 2020 को इसने सीबीएसई को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम से कई महत्वपूर्ण पाठों को हट दिया है। इन पाठों में महत्वपूर्ण आंदोलनों, घटनाओं अवधारणाओं और मूल्यों का वर्णन किया गया था, जो आधुनिक भारत के सापानिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन के चरित्र और लक्ष्यों को समझने के लिए महत्वपूर्ण थे। अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच सीबीएसई पाठ्यक्रम से इन पाठों को हटाने और अन्य बदलावों की निंदा करता है।

किसानों के मुद्दों पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का लाइव कार्यक्रम

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) द्वारा 31 जुलाई को ऑनलाइन फेसबुक कार्यक्रम 'किसानों का यह ऐलान, लेकर खेते पूरा दाग' विषय पर आयोजित किया गया। इसे अब तक विभिन्न फेसबुक पेजों पर 55 हजार से अधिक किसानों और समर्थकों द्वारा देखा गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, महाराष्ट्र के 'स्वाभिमान शेतकरी संगठन' के अध्यक्ष पूर्व सांसद राजू शेठटी ने कहा कि उन्होंने किसानों और विशेषज्ञों के साथ मिलकर तैयार किया गया कृषि उपज लाभकारी विधेयक लोकसभा में पेश किया था। जो कि लोकसभा में पास नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार द्वारा दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी नहीं दी गई तथा केंद्र सरकार ने दूध पाउडर के आयात तथा दुग्ध पदार्थों पर जीएसटी समाप्त नहीं किया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने देश के दुग्ध उत्पादक किसानों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की।

गन्ना किसानों को गन्ने के रेश में गन्ने 2 वर्षों से कोई एमआरपी नहीं बढ़ाने पर आपत्ति दर्ज करते हुए उन्होंने कहा कि उर्वरक और डोजल का दाम लगातार बढ़ रहा है ऐसी स्थिति में किसानों को भुगतान टुकड़ों (किलों), में देने की तथा व्याज प्रतिशत कम करने की मांग की जा रही है, जिसे एआईकेएससीसी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हरियाणा से 'अखिल भारतीय किसान महसंघ' के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रेम सिंह गहलवात ने कहा कि हरियाणा में 10 किसान संरक्षकों ने 23 जुलाई को मोर्चा कर तय किया है कि हम अपनी फसल का पूरा दाम लेकर रहेंगे। एमएसपी लागू करवाएंगे। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं पर अमेरिका का प्रभाव है तथा अमेरिका की कंपनियां दुनियाभर की जमीन को कब्जा चाहती हैं। उन्होंने कहा कि हम देश में कंसपैरिट को खेती नहीं करने देंगे।

पश्चिम बंगाल के एआईकेएससीसी इकाई के संयोजक कर्तिक पात्र ने कहा कि कुछ सुनिश्चित फल सब्जियों की छी नहीं किसानों को सम्पूर्ण उपज और सब्जियों की भी एमएसपी पर खरीद की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कंसपैरिट खेती संबंधित कानून देश में लागू हुआ तो किसानों के पास जमीन नहीं बचेगी। कॉर्पोरेट के हाथ में जमीन होगी, जिससे वे कृषि उत्पादों को विदेशों में निर्यात करेंगे। उत्तरप्रदेश से तरई किसान संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह दिक् ने कहा कि हम जब तक एकजुट होकर एमएसपी की मांग नहीं करेंगे तब तक सरकार नहीं देगी। मध्य प्रदेश से 'अखिल भारतीय किसान संघ' के प्रदेश अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने कहा कि जब किसानों की अपील महीने में अपनी उपज बेचने की बारी आई तब उस समय सरकार बिना दी गई और लॉकडाउन लगाने से एक महीने तक एक ही व्यक्ति ने सरकार चलाई। उन्होंने

संगठन/आंदोलन समाचार

कहा कि मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी और नकली खाद बेचने का धंधा चला रहा है। मध्य प्रदेश से 'राष्ट्रीय किसान मजदूर संघर्ष' के अध्यक्ष बहल राज ने कृषि अर्थशास्त्रियों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान परिवेश में मंडियों के निजीकरण से किसान को घाटा हो रहा है। कार्यक्रम का संचालन एआईकेएससीसी के वरिष्ठ ग्रुप के सदस्य डॉ. सुनीलम ने किया।

मध्य प्रदेश विद्युत संशोधन विधेयक- निजी कंपनियों को छूट और जनता की लूट

मौजूदा केंद्र सरकार विद्युत अधिनियम 2003 में व्यापक संशोधन करते जा रही है, जिससे निजी क्षेत्र की कंपनियों को सिर्फ मुनाफे से मालाब रहेगा पर उसका कोई ज़रियत नहीं होगा। इस नए विधेयक को 17 अप्रैल 2020 को प्रस्तावित किया गया, जब पूरा देश लॉकडाउन में फंसा हुआ था। इसके साथ ही लोगों को इस पर टिप्पणी करने के लिए महज 21 दिन दिए गए, खासकर जब लोगों के अधिकारों के स्वामन को निलंबित कर दिया गया था। भारी विरोध के कारण इसकी अवधि को 5 जून तक बढ़ाई गई।

विश्व बैंक, आईएमएफ, एशियन विकास बैंक तथा अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में तथाकथित ऊर्जा सुधारों के नाम पर केंद्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम-2003 लाया गया। इसमें विद्युत निगमक आयोग के बटन के अलावा तीन प्रमुख उद्देश्य थे। विद्युत मंडलों का विखंडन कर उत्पादन, वितरण एवं वितरण कंपनियों का निजीकरण, दूसरा विद्युत दरों में लगातार वृद्धि और तीसरा निजी और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। सन् 2000 में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का घाटा 2100 करोड़ रुपए था और 4892 करोड़ रुपए दीर्घकालीन ऋण था, जो पिछले 15 सालों में बढ़कर बिजली कंपनियों का घाटा और कर्ज 47 हजार करोड़ रुपए हो गया है। निजी कंपनियों से विद्युत खरीदी अनुबंध के कारण 2010 से 2019 अर्थात् पिछले नौ सालों में बिना बिजली खरीदे 6500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। मध्य प्रदेश में ऊर्जा सुधार के 18 साल बाद भी 65 लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं में से 6 लाख परिवारों के पास बिजली नहीं है और सभी गांव में बिजली पहुंचाने के सरकारी दावों के विपरीत मध्य प्रदेश के 54,903 गांवों में से अभी भी 3286 गांवों में बिजली नहीं पहुंची है।

- राज कुमार सिला, जयपुरी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ

वैश्विक महामारी के बीच दोहरी बाढ़ झेलती नर्मदा घाटी : एनबीए

मनावरा। नर्मदा घाटी के करीबन 50 गांव पूर्ण रूप से डूब गए व सैकड़ों गांवों में पानी घुस गया है। अचानक बाढ़ से

जनजीवन और सैकड़ों साल पुराने इन गांवों की खेती प्रभावित हुई है। जलस्तर बढ़ने और चारों तरफ पानी के लेने से किसानों की खेती फसल तो गई है, खेतों तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया और किसानों को फसलों की बर्बादी का मंजर देखते रहना पड़ा। मनावर तहसील का एकलबारा गांव से या सेमलदा गांव, हर जगह बड़ी दुर्दशा है। कचली गांव के 27 किसानों की जमीन डूब गई उनकी सर्वोच्च अदालत के आदेशानुसार 60 लाख रुपये हर्जाना आज तक नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं दिया गया है। कई किसानों के पास आज आजीविका का कोई भी साधन नहीं, शिवायत निवास प्राधिकरण की ओर से बेटों भाइयों को 60 लाख का आदेश प्राप्त हुआ है। आज दोनों भाइयों की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। लेकिन धनराशि कब मिलेगी, पता नहीं ?

आज की स्थिति में जब जल स्तर 13.5 मीटर है, नर्मदा घाटी के लगभग हर गांव तक पानी पहुंच चुका है, लेकिन विकास प्राधिकरण के पुनर्वास अत्युक्त, भूअर्जन अधिकारी जावजा लेने गांव नहीं पहुंचे। मौडिया इस लंबातर प्रसारित करने के बावजूद प्रदेश सरकार व बड़वानी, धार, अमिराजपुर, खरगोन के जिला प्रशासन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस वैश्विक महामारी के दौर में, जहां पिछले ही साल की बाढ़ से नर्मदा घाटी के लोग अभी तक खबर नहीं पाए हैं, ऐसे में इस दोहरी बाढ़ को झेलने के लिए सरकार व जिला प्रशासन ने लाखों किसानों, पशुओं, आदिवासियों, केवाठों, पशुओं, जीवंत फसल को अपने खल पर छोड़ दिया।

सरकार व जिला प्रशासन को जगाने हेतु, डूब प्रभावितों द्वारा गांव-गांव में क्रमिक अनशन सत्याग्रह शुरू किया गया। इस पर, बल प्रयोग करके सत्याग्रहियों को उखाड़ा गया और बाढ़ प्रभावितों पर केस दर्ज किए गए। हम, नर्मदा घाटी में प्रशासन और सरकार की इस लापरवाही की निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं प्रशासन दमन नीति छोड़, संवाद कर बाढ़ प्रभावितों का पूर्ण पुनर्वास सुनिश्चित करे।

सरदार सरोवर बांध से डूबे परिवारों को क्रमिक सत्याग्रह से जबरन हटाया

मनावरा। सरदार सरोवर जलाशय में 133 मीटर से ऊपर जलस्तर पहुंचने से गांव के साथ कृषि भूमि डूब रही है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का चुप रहना ही केंद्र और गुजरात सरकार के सामने समर्पण करना चिंताजनक है। सरदार सरोवर के विस्थापितों के गांव, मुहल्ले-एकलबारा, सेमलदा, गांगलौ, उदना, सेंगाव आदि गांवों के रास्ते डूब गए हैं तो साथ ही गजोपुर, धरमपुर के नर्मदा किनारे रहने वाले महुआरी के प्रकान डूबने की कगार पर हैं। सरकार का डाल रहा है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का कोई भी पुनर्वास अधिकारी डूब गांवों में भी नहीं जा रहे हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए डूब प्रभावित निवासी अहिंसक तरीके से क्रमिक अनशन पर पिछले दो दिन से बैठे हुए थे। उनकी मनावर नायब तहसीलदार हितेंद्र भावसा ने पुलिस बल के द्वारा जबरन हटाकर उनके पंडाल को भी तोड़ दिया गया और झंडे-बैनर भी निकाल लिए गए।

श्रद्धांजलि

हरीश अड्यालकर : आजीवन फैलाते रहे समाजवाद

हरीश अड्यालकर (३३) का जन्म (०३ सितंबर) समाजवादी विचार के एक प्रकाश स्तंभ का बुझ जाना है। कोरोना काल में उनकी और उनके बेटे की वृत्त (०४ सितंबर) समाजवादो परिवार के लिए बड़ी क्षति है। वे उस पीढ़ी के व्यक्ति थे, जिन्होंने विचार और संघर्ष को एक स्वयं जीया था। हालांकि ऐसे लोग पूरे देश में रहे हैं, लेकिन अब यह पीढ़ी धीरे-धीरे लुप्त हो रही है। हरीश जी के जाने से यह अहसास और तीव्र होत जा रहा है। वे नागपुर से गुजरने वाले तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं, लेखकों और बौद्धिकों के लिए संघर्ष की गुजनीति में भरोसा जगाते थे और विचारविमर्श प्रकटते लोगों को यह दिखाते थे। वे थे तो यह वकील होत या कि विचार है तो एक दिन वह अपने चाहने वालों की एक जगह बैठ करेगा, और जन लोग जुड़ेंगे तो वैसा समाज बनाने के लिए संघर्ष भी करेंगे।

ज. आंबेडकर की कर्मभूमि नागपुर में बाबा साहेब की इस महत्वपूर्ण बात को उन्होंने गैट में बांध रखा था कि कोई भी विचार सिर्फ पुस्तकों में पड़े रहने से मर जाता है। उसे आगे बढ़ाने के लिए सोचने-समझने वालों की जरूरत होती है। इसी को ध्यान में रखकर हरीश अड्यालकर पिछले 45 वर्षों से लोहिया अध्ययन केंद्र चला रहे थे। यशु लिमये, जार्ज फर्नांडीस, कर्पूरी ठाकुर, खुं ठाकुर, किशन पटनयक जैसे तमाम समाजवादी कार्यकर्ताओं और विचारकों से वे निजी तौर पर जुड़े थे और उनके साथ संघर्ष में उठते थे। रेलवे की नौकरी करते हुए अड्यालकर ने ट्रेड यूनियन की राजनीति की और उसी के साथ समाजवादी विचार से जुड़े। 1974 में जब जार्ज फर्नांडीस ने रेलवे की देखरेखी हड़ताल की तो उन्होंने उनका पूरा साथ दिया। उस समय बड़ीतर छानामाइट मामले के अभियुक्त जार्ज साहेब भूमिगत रहे और उन्होंने अड्यालकर के घर पर पनाह ली। ट्रेड यूनियन वाले नेना का तब हरीश जी में अखिर तक का। एक बिंदुस मराठी और ट्रेड यूनियन नेता की तरह उनकी बातचीत में बड़ी ठसक जीवन के आखिरी दिनों तक रही।

व्यावहारिक जीवन में संघर्ष की भाषा का प्रयोग और लेखन और

विचार-विमर्श में विषय नबोस्ता यह उनके व्यक्तित्व के दो पहलू थे। एक आयाम सड़क पर नहोवाजी और जेल यात्राओं से निर्मित हुआ था तो दूसरा अध्ययन मान से। एक सच्चा समाजवादो क्रांति ही ऐसे है। उसकी कथनी और कर्नी में कोई अंतर नहीं होना। हरीश जी भी लोहिया के उसी पथ के चली थे। अपनी नात रखने के लिए वे 'सामाज्यजन संदेश' नाम की पत्रिका निकालते थे और उन्होंने उसके 129 अंक संपादित किए थे। सन् 2010 में लोहिया जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर उन्होंने 'लोहिया: तब और अब' शीर्षक से एक विरोधांक निकाला, जो बहुत चर्चित रहा। उसमें देशभर के समाजवादियों से लिखावा और अच्छे संपादन और छापी के साथ प्रकाशित करने उसे दूर-दूर तक सुधी मासकों तक पहुंचाया। अध्ययन केंद्र चलाना, पत्रिका निकालना और बीच-बीच में खतियकारों, पत्रकारों और बौद्धिकों के व्याख्यान कराने के लिए संसाधन और ऊर्जा के कल से ललत थे, कई लोगों के लिए यह सोच पाना ही कठिन है। लेकिन जब हरीश जी जैसी वैचारिक प्रतिबद्धता हो तो लोग मिल ही जाते हैं मदद करने के लिए।

उन्हें नागपुर में भी वैसे लोगों का साथ मिल गया था और देशभर के लोगों से तो जुड़े ही रहते थे। बीच-बीच में उन्हें केंद्रीय हिंदी संस्थान, महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी का सहयोग भी मिला। राजनीतिक विचारों के लिए प्रतिबद्ध हरीश जी स्वयं नाटक भी लिखते थे और नागपुर आकाशवाणी में उसका निरंतर प्रसारण भी होता था। उनके जाने के बाद जो प्रकाश स्तंभ दुसा है, उसे जलने और फिर से चलाए रखने की चुनौती उस पीढ़ी के सामने है जो इजिजल हो चुकी है और जिसके भीतर विचारों और संघर्षों का वैरा समाव पाना कठिन है। फिर भी यह कहना युवा पीढ़ी के लिए अन्याय होगा कि वैसे लोग एकदम नहीं हैं। अड्यालकर के सपनों का समाजवादो समाज बनाने का प्रयास जारी रखना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सामयिक चर्चा हरीश अड्यालकर को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

-अरुण विप्राही

साथी ध्रुव सिंह परिहार नहीं रहे

समता संगठन से जुड़े साथी ध्रुव सिंह परिहार का 9 सितंबर को हृदयाघात से आकस्मिक निधन हो गया। कुछ दिन से पहले उन्होंने मुझे फोन किया और बताया कि उनका बेटा भास्कर छात्र नेता है और कॉलेज में विद्यार्थी युवजन सभा का मदन कर सक्रिय है। अपने जुझारू साथी के आकस्मिक निधन पर सजब सोक व्यक्त करती है।

-अरुण विप्राही

बत नब्बे के दशक की है रामपुर बधेलान जिला सतना के जमुना ग्राम में बाबूद फैक्ट्री के लगने का विशेष हुआ सभ्यता तैयार हो चुके प्लांट की पर्यावरण प्रदूषण के लोकातिथी मुद्दे के कारण से स्थानीय ग्रामवासियों ने बंद कराने का निर्णय लिया। इस आंदोलन के प्रमुख स्थानीय नेताओं में स्व. वृजकिशोर द्विवेदी बड़कामन, स्व. अरुण लखन जी, 'स्व. ध्रुव सिंह परिहार ध्रुव भाई', नेतृत्व विन्ध्य समाजवादी धारा के प्रमुख स्व. जमुना प्रसाद शास्त्री जी का था, प्लांट उखड़ने के कगार पर था। एक रात ग्राम दुआरी उन्मुलन (शिवपुरवा) रामपुर बधेलान में स्व. ध्रुव सिंह जी की कृतिया में अम्बेसडा

कर आकर सकती है। उसमें बाबूद फैक्ट्री के मैनेजर होते हैं। छोटे से गांव में नब्बे के दशक में एम्बेसडा का राशि 10 के लगभग आना, पूरे गांव में सनाका खिंच गया। मैनेजर जी 55-60 की उम्र के रहे होंगे आगे और ध्रुव सिंह जी से कहा कि बहुत अच्छा आंदोलन किया आपने। नेतृत्वही इतनी ही की जाती है मैंने बहुत नेगा देखे हैं, अटैप्पे बहाकन जोला के दिखाते हुए कहा, इसमें सगभ्य 20 लाख रुपये रहे होंगे कि इसे लीजिए और घर बनहने अपनी मां की सेवा करजिन जीवन को खुशहाल बनहने। स्व. ध्रुव सिंह जी जिनकी आर्थिक स्थिति कोई बेहतर नहीं थी अटैप्पे दुकरते हुए बोले-

"आपने मेरी विधायक सांसद देखे होंगे नेत नहीं।"

मैं मल्ला बांधी विन्ध्य भावे की परंपरा का व्यक्ति हूं, वह नही रूंगा और आंदोलन चलेगा, आंदोलन चला और शांतिपूर्ण रूप से चला एक फैक्ट्री 'पूजी' के खिलाफ फफल हुआ फैक्ट्री बंद हुई।

स्व. ध्रुव सिंह परिहार जी अब हमारे बीच नहीं हैं विनम्र श्रद्धांजलि।

-अरुण विप्राही

सामयिक चर्चा अब www.lohitoday.com पर भी पढ़ सकते हैं।

रिचर्ड ग्रोव : नहीं रहा पर्यावरण का इतिहासकार

प्रकृति, पर्यावरण और पर्यावरण-संरक्षण के इतिहास पर 'ग्रीन इंपीरियलिज्म' सरीखी चर्चित किताब लिखने वाले इतिहासकार रिचर्ड ग्रोव का जून 2020 में निधन हो गया। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में अल्फ्रेड क्रॉसबी, डोनाल्ड वॉस्टर्, जॉन मैकनिल, रोड्रिक नेश वगैरह जिन इतिहासकारों ने पर्यावरणीय इतिहास की ओर दुनिया भर का ध्यान खींचा। उनमें रिचर्ड ग्रोव उल्लेखनीय हैं।

स्विट्ज़ ग्रोव ने ससेक्स यूनिवर्सिटी में 'सेंट फॉर कल्ले एनवायरमेंट हिस्ट्री' की स्थापना की, जिसने वैश्विक परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय इतिहास के अध्ययन को बढ़ावा दिया। अपनी प्रभावशाली पुस्तक 'ग्रीन इंपीरियलिज्म' में रिचर्ड ग्रोव ने यह दर्शाया कि यूरोप से कहीं पहले एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के देशों में पर्यावरण से जुड़े सरोकारों और संरक्षण के प्रयासों का लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि अठारहवीं सदी के मध्य से ही वैज्ञानिक प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण से जुड़े मुद्दों को ओर रज्य और समाज का ध्यान खींच रहे थे।

कभी उपनिवेश रहे एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका के देशों में औपनिवेशिक शक्तियों ने अपनी साम्राज्यवादी नीतियों से किस तरह प्रकृति, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया। इसके क्या दुरगामी परिणाम निकले। इसके बारे में रिचर्ड ग्रोव ने अपनी पुस्तक 'इकोलॉजी, क्लाइमेट एंड एम्पायर' में गहराई से लिखा। रिचर्ड ग्रोव की यह किताब पंद्रहवीं सदी से लेकर बीसवीं सदी

तक पर्यावरण, जलवायु से जुड़े सरोकारों और उपनिवेशवाद के अंतर्गुणित इतिहास का सघन स्रोत देती है।

डच, फ्रांसीसी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनियों और आगे चलकर यूरोपीय साम्राज्यों ने अपने व्यापारिक पुनाफे के लिए कैरेब पर्यावरणीय संतुलन को तरह-तरह कर डाला, इस विषय में रिचर्ड ग्रोव ने विस्तार से लिखा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान समय में दुनिया भर में गहरते जा रहे जलवायु संकट की समझने के लिए हमें उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के इतिहास को भी जानना होगा। रिचर्ड ग्रोव ने परिस्थितिकीय साम्राज्यवाद (इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म) के इतिहास लेखन से जुड़ी इकहरी धारणाओं को जबरदस्त चुनौती अपने विचारोत्तेजक लेखन के जरिये दी।

जुलाई 1956 में पैदा हुए रिचर्ड ग्रोव की पढ़ाई छान और इंग्लैंड में हुई थी। उनके माता-पिता भी अपने समय के जाने-माने भूगोलापिद थे। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इतिहास में पीएचडी की। ये पर्यावरणीय इतिहास की प्रसिद्ध पत्रिका एनवायरमेंट एंड हिस्ट्री के संस्थापक-संपादक थे। साथ ही वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और आस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से संबद्ध रहे। भारतीय इतिहासकार विमोता दामोदरन उनकी पत्नी हैं। वर्ष 2006 में आस्ट्रेलिया में हुए एक सड़क दुर्घटना में रिचर्ड ग्रोव गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिससे उनकी कार्यक्षमता बुरे तरह प्रभावित हुई थी। पर्यावरण के अग्रतिम इतिहासकार रिचर्ड ग्रोव को सादर श्रद्धांजलि। **उपेन्द्र शंकर**

वार्ता के सभी ग्राहकों-पाठकों से निवेदन है कि अगर आपके पास ईमेल आईडी या व्हाट्स ऐप नंबर है तो कृपया उपलब्ध करा दीजिए ताकि आपको वार्ता ऑनलाइन भेजी जा सके।

आप अपनी ग्राहकी का नवीकरण भी कर लें। प्रकाशित वार्ता डाक से भेजी जाएगी। इसके साथ ही वार्ता को आर्थिक सहायता देने में सहयोग करें।

मत=विमत

सामयिक वार्ता

R.N.I. पंजीयन संख्या 31211/77

साथी स्वाति स्मृति अंक पर पाठकों के विचार

स्वाति जी की स्मृति में एक पूरे अंक को समर्पित करने आपने सरासरी काम किया। हमें 1976 से जीवन के अंतिम दिनों के बीच उनकी विद्वत्ता से लेकर करीब तक विकट से जयने का अस्मर रहा। समाजवादी अध्ययन के तब तक आवास से ही संचालित हुआ करता था। उन्होंने करीब विश्वविद्यालय अध्यापक संघ के उपाध्यक्ष के रूप में हमारा नेतृत्व भी किया। हम शिक्षक के रूप में एक दशक तक सहकर्मी रहे। हमारी पारिवारिक निकटता थी। इसीलिए उनके व्यक्तित्व और कर्म से संबंधित अनेकों स्मृतियाँ हैं। अन्तविदा, स्वाति जी!

-अमरेंद्र कुमार, समाजवादी और जेएनयू से सेवानिवृत्त प्रोफेसर

सामयिक वार्ता पत्रिका का 'साथी स्वाति स्मृति अंक' मिला। पत्रिका में उनके बारे में इतना कुछ पढ़कर मन क्रुद्ध और बेचैनी से भर गया। मुझे इसकी पीड़ा और गहराई से यह कि इस विशेष अंक के लिए मैं कुछ भिन्न नहीं सका। दरअसल मेरी उनसे मुलाकात इतनी संक्षिप्त और सहज रही कि उसे शब्दों में कह पाने की कठिनाई से मैं मुक्त हो नहीं हो पाया। बनारस में अखिल भारत शिक्षा अधिकार पंच के आयोजनों के संदर्भ में मेरे उनसे फ़नी बात हुई थी। कुछ वर्षों के छात्रों की शिबिर में शामिल करना था, फिर सतनाथ सम्मेलन में मुलाकात हुई, वहाँ उत्तर प्रदेश में समान शिक्षा आंदोलन के संघ से काम करने का तब हुआ था।

इलाहाबाद के सम्मेलन और दिल्ली की रेलों की तैयारी के संदर्भ में मुलाकात होती रही। स्वाति जी से मेरी सबसे जीवंत और अखिर मुलाकात लखनऊ की थी। 13 जनवरी 2019 को श्री जय नारायण स्मार्तकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ द्वारा आयोजित 'भाषा शिक्षा और संविधान' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में यह मुलाकात हुई थी। वहाँ हम अधिक जीवंत और बेचैनी से बातें कीं। जो प्रसाद जी, अफलातून जी और स्वाति जी। कार्यक्रम पूरा हो जाने के बाद हम कॉलेज के गेट पर चटोटे बैठे रहे और सेमिनार की बहसों को व्यावहारिक और जर्मनी आंदोलन का रूप देने तथा समान शिक्षा आंदोलन, उत्तर प्रदेश की मतभेद करने का कार्यक्रम चलाते रहे। असल में स्वाति जी की सहजता हमारे लिए बड़ी चुनौती रही है। उनके व्यक्तित्व में कोई दोष नहीं था, कोई दोष नहीं था और आज के संगठनों के तथाम अनुशासनों की तरह का नीकशाहना स्वेच्छा नहीं करती। आप अपने को कितना भी चतुर क्यों न समझें हों, उनके साथ वादाविरोधाधी नहीं कर सकते थे, उनकी राजनीतिक और सामाजिक अवस्थाओं के साथ सापेक्षता नहीं कर सकते थे।

उन्होंने हमें उस धर्म और सहजता की व्यावहारिक प्रेरणा दी, जो किसी संन्यासी लहंगे में जीत के लिए अभयार्थ होती है। आज जब ये भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं है फिर भी निरंतर हमारी निराहवाँ कसती प्रतीत होती है और होती रहेंगी!

-डॉ. चतुरान्व अग्रवाल, समान शिक्षा आंदोलन, उत्तर प्रदेश

राय-आलोचना देने में सक्षम लड़के। आरंभ में पढ़ेंगे। बेशक, काफी समृद्ध अंक है। चरम पर पूरे पर खाल थी। आपकी बेहतन सकारा हुआ है। हम दोनों साथ से बढ़ेंगे। जोदिएर मुनासक।

-अनिल सदनोपाल, जवाहरिअर्ध, अन्धक मंडल सदन

स्वाति जी की यह लोगों के मन में प्रकाशपूर्ण और गहरी है। अंक देख कर अच्छा लगा।

स्मरणेन वार्ता, पूर्व विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वि. स्वाति जी का बहुत ही व्यक्तित्व जीवंतता के साथ उभरता है। उनके जीवन में जन्म खुद को धी धीरे से बजबज करके जाता है। संपर्काधीन क्षय साधक हुआ है।

-हर्षेन्द्रशर्मा, प्रसिद्ध कवि

शुक्रिया। स्वाति से जुड़े हुए इतने सारे लोगों से जुड़ना भी साथ में तो

रहा है।

-महेश्वर, प्रसिद्ध इतिहासकार कवि एवं प्रोफेसर

सामयिक वार्ता के डॉ. स्वाति अर्द्धांगिणी अंक प्रकाशित करने के लिए धन्यवाद। इसके साथ आज मुझे फिर से एक अलग तरह की भावना का अनुभव हो रहा है।

-विमलेश कुमार, अकादमिक, लखनऊ विश्वविद्यालय

नमस्ते, अफलातून जी। पीछेछाप पर एक नजर डाली। बहुत अच्छा बना है। पृष्ठ पढ़ने में ऑनलाइन बहुत मुश्किल हम जैसे कामजों के आदी लोगों को, लेकिन कुछ पन्ने पढ़ते-पढ़ते। कृपया मेरे लिये 5 नवंबर को पत्रिका की रखें, मैं उन्हें आते-जाते आपसे करीब ले लूंगा।

-जमकी अग्रवाल

मुझे यह संकलन बेजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वालन में प्यार का एक अंक है- मैं कब पर स्वाति को प्यार से तस्वीर को बहुत पसंद करती हूँ- वह उनके व्यक्तित्व की अच्छी तरह से उजागर करता है। मैं पृष्ठ पढ़कर चर में प्रतिक्रिया चुनूँ।

-अनु नेतृत्वोपयोग

यह एक सुंदर संकलन है। सारा करने के लिए धन्यवाद। मुझे बकीर है कि हा कोई इसे पढ़कर भावुक होगा।

-विमलेश

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह उनके जीवन और काम का वास्तविक आकलन है। मैं फिर से उन अन्तर्दृष्टियों के कुछ शब्दों की पुनः वाद दिलाने के लिए आपका आभारी हूँ। मैं संपर्क में रहूँगी।

निकल

प्रभावशाली प्रकाशन। यह सब पढ़ने के लिए काफी समय लगेगा। अफलातूनजी, मैंने अपना लेख पढ़ा जो आपने पत्रिका में प्रकाशित किया है। इसमें इसे साहित्य करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपको अपनी ओर से पुरे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ।

-सुपुल मोदी

धन्यवाद, अफलातूनजी। यादों का किटना खूबसूरत सेट। मैंने इसे स्कैन किया, लेकिन मेरी हिंदी बहुत खराब होने के कारण इसे पढ़ने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी। मैं इसे उन शब्दों को भेजूंगा जो स्वाति को जानते थे।

-रंजु शर्मा

वार्ता की प्रीट मिली। स्वाति जी को सम्मान। अच्छा प्रकाश। जो इसकी हकदार है। समूह के अस्तित्व में आने के बाद से उन्होंने समाजवादी जन परिषद के लिए ईनामवरी से काम किया।

-श्रीतीर्थ आचार्य, धुमकेसर

आदरणीय स्वाति जी पर स्मृति अंक निकालने के लिए साधुवाद। वे एक अविस्मरणीय साधक-राजनीतिक कार्यकर्ता थीं। सामयिक वार्ता में उनके लेख अक्सर पढ़ता था और उनकी जिजीविषा से बहुत प्रेरणा मिलती थी। उनकी स्मृति को सादर नमन।

-प्रवीण मल्लोहा, इंदौर

स्वाति जी की स्मृति में निवेदन की प्रति प्राप्त की। उनके बारे में पढ़ता प्रेरणादायक रहा। यह अंक उनके प्रति गहरी भावना को उजागर करता है। यह उनके प्रति सच्ची अर्द्धांगिणी है। आपके दुख और दुःख संकल्प में हम आपके साथ हैं।

-गणेश देवी, अन्धक, सह सेना बल

स्वामी, प्रकाशक, पुस्तक मालिक कुमार प्रसाद सिंह द्वारा 14, समरपुर जंगम, बाँडवन्ध, विल्ली-110091 से प्रकाशित और वीप कलर स्कैन (प्र.)

लिमिटेड, एम-5, गली नं. 4ए, ई-इस कॉलोनी इंडस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली-95 से मुद्रित। संपादक : अफलातून